शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 241 | गुवाहाटी | सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

असम में पहली बार घुसपैठ के भय से मुक्ति का भरोसा, जीत की हैट्रिक की... पेज 2
ओवैसी के असम दौरे का विरोध, नेतृत्व बदलाव की खबरों को बताया फर्जी पेज 3
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल स्वावलंबी बन रहा राजस्थान पेज 5
एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2027 पर हार्दिक पांड्या की नजर, 10 ओवर गेंदबाजी... पेज 7

असम में बीफ पर सियासी बवाल, सीएम हिमंत का एजेपी उम्मीदवार पर निशाना, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति में बीफ विवाद को लेकर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने असम जातीय परिषद (एजेपी) की उम्मीदवार कुंकी चौधरी और उनकी मां सुजाता गुरुंग चौधरी पर कथित रूप से बीफ खाने के आरोपों को लेकर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। इस तरह के आरोपों ने असम विधानसभा चुनावों से पहले एजेपी और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि असम में बीफ खाने की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।उन्होंने दावा किया कि उनके आग्रह के बाद कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब बीफ की बजाय भैंस का मांस खा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में लागू पशु संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की सजा हो सकती है। शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी गाय का मांस खाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाय का मांस खाने वालों को मैं नहीं बख्शने -शेष पृष्ठ दो पर

कांग्रेस का हिमंत की पत्नी पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति छिपाने का आरोप

नई दिल्ली (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया है। पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास विदेशों में संपत्तियां होने और इनका विवरण चुनावी हलफनामे में नहीं देने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी -शेष पृष्ठ दो पर

पवन खेड़ा के विरूद्ध 48 घंटें में दर्ज होंगे फौजदारी एवं दीवानी मामले : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में जारी विधानसभा चुनावों के बीच रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है, तो झुकना सीखो। क्यूंकि जो झुकते नहीं, समय की हवा उन्हें झुका देती है।
– ईश्वर चंद्र विद्यासागर

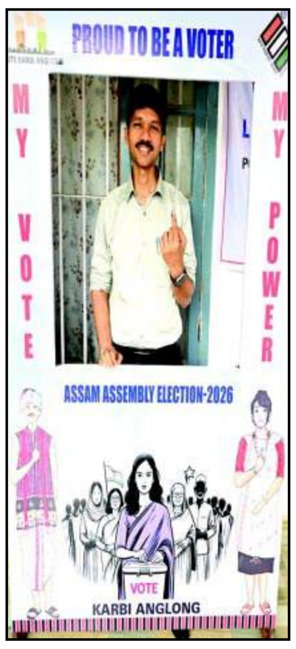

कार्बी आंग्लांग के जिला निर्वाचन अधिकारी अरण्यक सैकिया ने आज डीसी कार्यालय में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाला।

डॉ. शर्मा ने दिसपुर में बरदलै के लिए रैलियां की

गुवाहाटी में दो मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को दिसपुर में भाजपा के मुख्य चुनावी मुद्दों को केंद्र में ला दिया। एक महत्वपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए, शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार प्रद्युत बरदलै के लिए जोरदार समर्थन जताया , जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, और उनके इस बदलाव को बदलते राजनीतिक परिदृश्य में एक स्वाभाविक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस में उनके जैसे लोगों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। इसलिए, उन्हें चुनाव जिताने में मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। रैली में *आको एबार मोदी सरकार* के नारे गूंज रहे थे, और शर्मा ने शासन और कार्यों पर जोर देते हुए अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की, साथ ही शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए वादे भी किए। इस सूची में सबसे ऊपर स्वास्थ्य सेवा थी। मौजूदा बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों को उजागर करते हुए, शर्मा ने घोषणा की कि गुवाहाटी में -शेष पृष्ठ दो पर

हिमंत विश्व शर्मा को नहीं बख्शेंगे सत्ता में आते ही भेजेंगे जेल : राहुल

विश्वनाथ। असम के विश्वनाथ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर कड़ा हमला किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति में बाहरी दखल का आरोप लगाते हुए कहा कि असम की कमान असल में दिल्ली के हाथों में है। उन्होंने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर संघर्ष और तेज करेगी। असम की रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं और नरेंद्र मोदी व अमित शाह आपके मुख्यमंत्री को कंट्रोल कर रहे हैं। -शेष पृष्ठ दो पर

असम विधानसभा चुनाव 2026

722 में से 102 पर क्रिमिनल केस : एडीआर

गुवाहाटी। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राज्य की विधानसभा के 126 सदस्यों का चुनाव होगा। वोटों की गिनती होगी और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने खुद का शपथ पत्र जमा किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बताया है कि चुनाव लड़ रहे 722 में से 102 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस घोषित किए हैं। इसका मतलब है कि 14 प्रतिशत उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस हैं, जबकि 82 या 11 प्रतिशत के -शेष पृष्ठ दो पर

जुबीन को जल्द मिलेगा न्याय, 10 दिनों में होगा चार्ज फ्रेम : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि जुबीन गर्ग से जुड़े मामले में आगामी 10 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले में तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कुंकी चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कामाख्या मंदिर, माजुली और बटद्रवा थान जैसे पवित्र स्थलों पर गोमांस का सेवन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कुंकी चौधरी स्वयं को सनातनी मानती हैं, तो उन्हें अपने माता-पिता के कथित कृत्य से सार्वजनिक -शेष पृष्ठ दो पर

असम चुनाव : चुनाव आयोग की कार्रवाई में 97 करोड़ रुपए बरामद, 126 सीटों पर ईवीएम तैयार

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किए जाने के मद्देनजर, भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि अधिकारियों ने राज्य में अब तक 97 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की है। जब्त की गई वस्तुओं में 4 करोड़ रुपए नकद, 20 करोड़ रुपए की शराब, 56 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 4 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 13 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। असम उन प्रमुख चुनावी राज्यों में से एक है जहां 26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद प्रवर्तन एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। ये जब्ती एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसके तहत असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित चुनाव वाले राज्यों में 650 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित -शेष पृष्ठ दो पर

अफगानिस्तान में बारिश बाढ़ का कहर, 77 मौतें व सौ से ज्यादा घायल

काबुल। अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच देश के कई प्रांतों में आई बाढ़ से कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के कारण हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। करीब 3,400 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इसके अलावा हजारों एकड़ कृषि भूमि भी -शेष पृष्ठ दो पर

सोनोवाल ने टिहू चुनाव में पटवारी का समर्थन किया

एनडीए की 100 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी की

नलबाड़ी। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने रविवार को टिहू में चंद्रमोहन पटवारी के लिए प्रचार किया और 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनावों में एनडीए की संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए पिछले शासन संबंधी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। टिहू हाई स्कूल के खेल के मैदान में विजय संकल्प की रैली को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने मतदाताओं से *राष्ट्रीय चेतना* की भावना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने और ऐसे नेतृत्व का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसने उनके अनुसार, असम के विकास और स्थिरता के लिए लगातार काम किया है। पाटोवारी की प्रशंसा करते हुए सोनोवाल ने कहा कि चंद्रमोहन पाटोवारी ने उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को ईमानदारी और समर्पण के साथ -शेष पृष्ठ दो पर

असम चुनाव से पहले यूपी से *रिवर्स माइग्रेशन*

नई दिल्ली। असम चुनाव में इस बार यूपी की ओर से बम्पर वोटिंग होने की संभावना है। इसकी वजह है कि अचानक लखनऊ की झुग्गियां खाली होने लगी हैं और स्टेशन पर असम जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। ये चुनावी *रिवर्स माइग्रेशन* है, जिसके पीछे कहीं वोट कटने का डर है तो कहीं नागरिकता जाने का। कुछ लोगों का कहना है कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन जाने वालों की भीड़ कुछ ज्यादा उत्साहित करने वाली है। लोकतंत्र में बम्पर वोटिंग एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है बशर्ते कि वो डर और आशंका की वजह से ना हो। ये पलायन वोट डालने के लिये तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या हैं लोगों से ही जान लेते हैं। इन्द्रा नगर की -शेष पृष्ठ दो पर

अगर *नोटा* जीत जाए तो कौन बनेगा विधायक ? ...जानें चुनाव आयोग के नियम

नई दिल्ली। असम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विभिन्न पार्टियों ने चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मतदान के दिन ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ एक विकल्प नोटा (नन ऑफ द एबव) का होता है। आम लोगों के मन में नोटा (नन ऑफ द एबव) या *नन ऑफ द एबव* को लेकर बहुत उत्सुकता है खासकर - क्या होगा अगर नोटा को किसी चुनाव क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स से ज्यादा वोट मिल जाएं? तो क्या उस इलाके में कोई एमएलए नहीं होगा? अगर नोटा को इलेक्शन में किसी सीट पर सभी कैंडिडेट्स से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो कानूनी क्या होगा? क्या उस इलाके के सभी कैंडिडेट्स हार जाएंगा? या फिर दोबारा इलेक्शन होगा? नोटा को भारतीय चुनाव में पहली बार 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शुरू किया गया था। इसका मकसद वोटर्स को *राइट टू रिजेक्ट* का अवसर देना और पॉलिटिकल पार्टियों को ईमानदार कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने के लिए -शेष पृष्ठ दो पर

व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग! सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास रविवार तड़के फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया, हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, घटना लाफाएते पार्क के आसपास रात करीब 1 बजे हुई, जो व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीक्रेट सर्विस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स पार्क पुलिस मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। सीक्रेट सर्विस के कम्युनिकेशन चीफ ऑथोरिटी गुगलाइमी ने बताया कि अधिकारियों -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

ईस्टर के पावन अवसर पर सीएम ने दी शुभकामनाएं

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को ईस्टर के पावन और हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर राज्य के ईसाई समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने इस दिन की पवित्रता और महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्व लोगों के विश्वास को नई शक्ति प्रदान करे और प्रत्येक हृदय में आशा का नया प्रकाश जगाए।

असम में पहली बार घुसपैठ के भय से मुक्ति का भरोसा, जीत की हैट्रिक की तैयारी में भाजपा

गुवाहाटी। हाल के वर्षों में कई राज्यों में चुनाव के दौरान घुसपैठ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लग गया है। पर असम में यह आजादी के बाद से ही बड़ा मुद्दा रहा है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलै ने 1950 में घुसपैठ के खिलाफ कड़ा कानून लाकर इससे निपटने का भरोसा दिया था। लगभग 75 साल बाद पहली बार असम के लोगों में इससे मुक्ति का भरोसा जगा है। भाजपा इस भरोसे से सहारे असम में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि उसके घोषणापत्र में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर है और नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में वह यूसीसी लाने के साथ ही घुसपैठियों को पूरी तरह से बाहर निकालने का वायदा कर रही है। दरअसल, नामघरों से अवैध कब्जा हटाने के साथ-साथ 1.50 लाख बीघा जमीन को मुक्त कराकर हिमंत विश्व शर्मा की भाजपा सरकार घुसपैठियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का संकेत देने में सफल रही है। देश में असम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 1951 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) लागू हुआ। लेकिन कालांतर में यह भरोसा क्षीण पड़ता गया और 1979 में मंगलदै लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में 47 हजार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के बाद असम में हिंसक आंदोलन शुरू हुई था, जो असमी अस्मिता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वायदे के साथ असम समझौते के बाद खत्म हुआ था। लेकिन कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण घुसपैठ की समस्या बनी रही। गुवाहाटी के पलटन बाजार में पुस्तैनी दुकान चलाने वाले अरुण गोगोई के अनुसार, इससे पहले अवैध घुसपैठ केवल चुनावी मुद्दे तक सीमित रहा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इससे मुक्ति दिलाने का वायदा करती रहीं। उनके अनुसार पहली बार यह अहसास हो रहा है कि असम में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सकता है। वैसे पहले से रह रहे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के भाजपा के वायदे पर वह अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों, जिन्हें यहां *मियां* मुसलमान भी कहा जाता है, के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा राष्ट्रीय मीडिया में भले ही आलोचना के घेरे में रहते हों और मियां मुसलमानों को गोली मारने के वीडियो असम भाजपा को डिलीट करना पड़ा हो, लेकिन असम में इसे अवैध घुसपैठ को खत्म करने की शर्मा की कठोर नीति के रूप में देखा जाता है। वहीं शर्मा अवैध घुसपैठ को मिया मुसलामनों तक सीमित करने में काफी हद तक सफल रहे है और बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हिंदू राजनीति विमर्श में नहीं हैं। जबकि 1985 के असम समझौते के क्लाउज छह में स्पष्ट रूप से 24 मार्च 1971 के बाद आए अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का प्रविधान है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। सीएए ने 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता का रास्ता भी खोल दिया है। वहीं 40 फीसद मुस्लिम आबादी और 126 में से 23 विधानसभा सीटों के मुस्लिम बहुल होने के कारण कांग्रेस अवैध घुसपैठ के खिलाफ हिमंत विश्व शर्मा की तरह कड़े बयान देने की स्थिति में नहीं है।

बंगाईगांव रैली में भाजपा के कैंपेन सॉन्ग पर जमकर थिरके सीएम हिमंत

बंगाईगांव। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को बंगाईगांव में चुनावी रैली में भाजपा के कैंपेन सांग पर डांस करते देखा गया। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के जनसंपर्क अभियान का जश्न मनाने में पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ जमकर झूमे। शर्मा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तीन ऑफिसियल थीम सॉन्ग रिलीज किए थे, जिनका मकसद भाजपा के विजन को लोगों तक पहुंचाना और मतदाताओं से भावनात्मक रूप से जुड़ना था। शर्मा ने कहा कि चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई थीम गीत तैयार किए हैं। इन गीतों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही लिखा और बनाया है। इन गीतों में से एक असोमोर सुराख्या, बिकाशोर प्रतिज्ञा जिसका मतलब होता है असम की सुरक्षा, विकास का वादा, जिसे विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा ने लिखा और बनाया था, और इसे राकेश रियान ने गाया था। एक और गीत *लागे लागे लागे आको एबार भाजपा सरकार* जिसका मतलब चाहिए, चाहिए, चाहिए, फिर एक बार भाजपा सरकार जिसे सरकारी ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो के अध्यक्ष विद्यासागर बोरा ने लिखा था और इसे अरण्यम दोवाराह ने गाया था। भाजपा प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने कहा कि इन गीतों का मकसद सरकार के विकास, सुशासन और कल्याणकारी पहलों का संदेश हर मतदाता तक पहुंचाना है। असम राज्य विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, और इनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को बिहू और दुर्गा पूजा के दौरान हर व्यक्ति को एक-एक फ्री एलपीजी सिलिंडर देने का वादा किया है। इस घोषणा के समय पूरे राज्य में कुकिंग गैस वितरकों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही थीं। शर्मा शनिवार को चराइदेउ जिले के महमोरा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सूरज दिहिंगिया के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में उन्होंने कहा कि बिहू और दुर्गा पूजा में हम लोगों को एक-एक गैस सिलिंडर फ्री में देंगे। इन दो सिलिंडरों का भुगतान मामा करेंगे।

पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में बड़ी चेतावनी, 4 मई के बाद टीएमसी के हर पाप का होगा हिसाब

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कूचबिहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कूचबिहार में उमड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि बंगाल में अब टीएमसी का समय समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की रैली का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से शुरू हुआ परिवर्तन का महाअभियान अब पूरे बंगाल में फैल चुका है। ब्रिगेड ग्राउंड के उत्साह ने टीएमसी के *सिंडिकेट* को डरा दिया है और आज कूचबिहार की जनता ने उस बदलाव पर अपनी मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने टीएमसी और भाजपा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक तरफ टीएमसी का डर है, तो दूसरी तरफ भाजपा का भरोसा। उन्होंने कहा कि एक ओर टीएमसी के *कटमनी* और भ्रष्टाचार का आतंक है, तो दूसरी ओर विकास की रफ्तार वाली भाजपा की गारंटी। एक ओर घुसपैठियों को बसाने की साजिश है, तो दूसरी ओर उन्हें बाहर निकालकर बंगाल को सुरक्षित करने का हमारा संकल्प है। संदेशखाली की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भावुक लहजे में कहा कि एक तरफ बेटियों पर अत्याचार और उनकी चीखें हैं, तो दूसरी तरफ नारी शक्ति को सुरक्षा और सम्मान देने वाली मोदी की गारंटी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं कि चुनाव के बाद इनके हर पाप का हिसाब होगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा और चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो, न्याय होकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल की कानून-व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है और जिस बंगाल में कभी लोग रोजगार की तलाश में आते थे, आज उसे पलायन का केंद्र बना दिया गया है।

अमेरिका की इकोनॉमी पर बड़ा संकट! अमेजन एयर लाइंस ने बढ़ाया चार्ज, महंगाई बेकाबू

वाशिंगटन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई अब खुद अमेरिका के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपनी डिलिवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की घोषणा की है। वहीं, कई एयरलाइन कंपनियों ने भी सामान ले जाने की फीस बड़ा दी है। अमेरिकी परिवहन संघ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को पेट्रोल की औसत कीमत 4.09 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है। यह युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की तुलना में एक डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है, जो अगस्त 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। डीजल की हालत और भी खराब है। पिछले साल जो डीजल 3.64 डॉलर था, वह अब बढ़कर 5.53 डॉलर प्रति गैलन हो गया है। डीजल की कीमतों में इस उछाल का सीधा असर खेती, निर्माण और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। बढ़ती लागत को देखते हुए अमेजन 17 अप्रैल से अपने सेलर्स पर 3.5 प्रतिशत का फ्यूल सरचार्ज लगाने जा रही है। इसी तरह, अमेरिकी डाक सेवा ने भी अस्थाई रूप से 8 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है। यदि मंजूरी मिली, तो यह 26 अप्रैल से लागू होकर जनवरी 2027 तक जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, तो अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है। आर्थिक मामलों की जानकार रैशल जिएम्बा का कहना है कि यह एक ग्लोबल मार्केट है और अमेरिका इस महंगाई से बच नहीं पाएगा। उनके अनुसार, एक्सपर्ट्स की चिंता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

पृष्ठ एक का शेष

असम में बीफ पर सियासी...

वाला। कानून के अनुसार, मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गरमा गया है। वहीं एजेपी ने इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बताया है।बीफ विवाद के बीच कुंकी चौधरी को गुवाहाटी में एक रैली के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। एक वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी *एजेपी गो बैक* के नारे लगाते दिखाई दिए। चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा के आईटी सेल ने उनका एक एआई-जनित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इतनी बेताबी क्यों? भाजपा का आईटी सेल ऐसे वीडियो बनाने में इतना पैसा और मेहनत क्यों खर्च कर रहा है? अगर उन्हें वीडियो बनाना ही है, तो वे मेरे घर आ सकते हैं और मैं बयान दूंगी। इसी बीच सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने जोरहाट में एक बड़ा रोड शो किया, जिसे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का गढ़ माना जाता है। गोगोई जोरहाट सीट से सांसद हैं, लेकिन मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। रोड शो के दौरान शर्मा ने दावा किया कि जोरहाट में लोगों का भारी समर्थन गोस्वामी के साथ है और वह बड़े अंतर से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि लोग विकास के लिए वोट देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अपर असम की सभी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। जोरहाट में गोस्वामी की लोकप्रियता और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ उनके लंबे संबंधों को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि गोस्वामी अपने पक्ष में वोटों को कैसे एकजुट करते हैं। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

कांग्रेस का हिमंत की ...

मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कथित दस्तावेजों की फोटोकॉपी दिखाते हुए कहा कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ-बारबुडा और मिस्त्र के पासपोर्ट हैं। यूएई का पासपोर्ट 14 मार्च 2022 को जारी हुआ और 13 मार्च 2027 तक वैध है, एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट 26 अगस्त 2021 को जारी हुआ और 25 अगस्त 2031 तक वैध है, जबकि मिस्त्र का पासपोर्ट 13 फरवरी 2022 को जारी हुआ और 12 फरवरी 2029 तक वैध है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, ऐसे में यह मामला गंभीर जांच का विषय बनता है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की राजनीति एक ओर जहां धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित बताई जाती है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी के पास कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट होना कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइयां शर्मा के नाम पर दुबई में दो संपत्तियां हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी और अपने परिवार की चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा हलफनामे में दे। ऐसे में इन संपत्तियों का जिक्र न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। खेड़ा ने कहा कि अमेरिका के वायोमिंग में रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़ी एक कंपनी संचालित है, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी जुड़े हैं। इस कंपनी का बजट 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और इसमें परिवार के सदस्यों के बीच लगभग 52,000 करोड़ रुपए के हिस्से का उल्लेख किया गया है। पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि वायोमिंग जैसे स्थान का चयन इसलिए किया गया क्योंकि वहां कर संबंधी नियम अपेक्षाकृत सरल हैं और संपत्तियों को छिपाने के आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से पहले दो दिन तक उनका सत्यापन किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस मामले में संज्ञान लेने और हलफनामे में कथित जानकारी छिपाने के आरोपों की जांच करने की अपील की।

पवन खेड़ा के विरूद्ध ...

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर कई पास्पोर्ट रखने का आरोप लगाया गया है, जिसे एआई के जरिए बनाए जाने की बातें कही गयी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जारी अपने संदेश में कहा है कि पवन खेड़ा की रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरे असंतोष और घबराहट को दर्शाती है। जैसे-जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके कमजोर होते जनाधार को ही उजागर करते हैं। मैं उनके द्वारा लगाए गए हर आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। उनके इन गैर-जिम्मेदाराना और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक बार जब अदालत में सच्चाई साबित हो जाएगी, तो पवन खेड़ा को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, और कानून अपना काम करेगा। असम की जनता ऐसे दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होगी। हम पूरी तरह से केंद्रित, दृढ़ निश्चयी और जनता से 100 से अधिक सीटों का निर्णायक जनादेश हासिल करने के प्रति आश्वस्त हैं।

डॉ. शर्मा ने दिसपुर ...

दो नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिससे कुल संख्या चार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन रात में आमतौर पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने शहर में दो और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने वार्ड स्तर पर विकास योजनाओं का भी एलान किया और वादा किया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो इस साल 60 वार्डों के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस वादे को जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के सीधे प्रयास के रूप में पेश किया गया। अभियान में एक नरम, समुदाय-केंद्रित पहलू जोड़ते हुए, शर्मा ने कहा कि सरकार गुवाहाटी के हर वार्ड में संगीत स्कूल और इंटरनेट-सक्षम पुस्तकालय खोलने पर भी विचार कर रही है। लेकिन यह रैली सिर्फ विकास के बारे में नहीं थी। शर्मा ने गुवाहाटी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे गोमांस विवाद पर भी अपनी राय रखी, जिससे उनके भाषण का राजनीतिक प्रभाव और भी बढ़ गया। किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना, उन्होंने मतदाताओं से उन उम्मीदवारों को खारिज करने का आग्रह किया जिनके परिवार कथित तौर पर गोमांस का सेवन करते हैं, और इस मुद्दे को असमिया पहचान और सामाजिक मूल्यों से जुड़ा मुद्दा बताया। मुसलमानों ने मुझे व्हाट्सएप पर बताया कि वे इस ईद पर भैंस का मांस खा रहे हैं। ऐसे समय में जब असम के मूल निवासी मुसलमानों को यह बात समझ आ गई है, अगर असम के लोग भी ऐसा करने लगें तो क्या असमिया समाज टिक पाएगा? मैं इसी कारण से मुख्यमंत्री बना हूं, उन्होंने कहा। एक तरफ विकास के वादे और दूसरी तरफ पहचान की राजनीति के साथ, शर्मा की दिसपुर रैली ने भाजपा की दोहरी रणनीति को उजागर किया क्योंकि चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है।

हिमंत विश्व शर्मा को...

उन्होंने आरोप लगाया कि असम की सरकार को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि दिल्ली से अमित शाह चला रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ी गलती की है। अब उनके परिवार को भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंत विश्व शर्मा को माफी मांगने पर भी नहीं छाड़ेंगे और जेल भेजकर दम लेंगे। चुनावी सभा के साथ-साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी केंद्र सरकार के वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए ये केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार इस मामले में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुरक्षा को सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पीड़ित महिलाएं मदद के लिए भटक रही हैं लेकिन सरकार ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में भी वन स्टॉप सेंटर की बदहाली का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि इन सेंटरों में ताले क्यों लगे हैं और वहां स्टाफ की कमी क्यों है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर पांच में से तीन महिलाओं तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है। राहुल ने बजट के कम इस्तेमाल और देशभर से आ रही शिकायतों पर सरकार की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से पिछले पांच वर्षों में खुले नए सेंटरों और वहां खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राहुल गांधी के सवालों का लिखित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के तहत ये सेंटर महिलाओं को चिकित्सा और कानूनी मदद मुहैया कराते हैं। सरकार के मुताबिक, साल 2015 से अब तक करीब 13.37 लाख महिलाओं की सहायता की गई है। मंत्री ने कहा कि इन सेंटरों को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और नीति आयोग ने इस योजना के प्रदर्शन को संतोषजनक माना है। हालांकि राहुल गांधी ने सरकार के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

722 में से 102 पर...

खिलाफ गंभीर क्रिमिनल आरोप हैं। 2021 के असेंबली चुनाव में, 941 उम्मीदवारों में से 138, या लगभग 15 प्रतिशत ने क्रिमिनल केस बताए थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (आईयूडीएफ), जो असम विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस मामले में शीर्ष पर है। इसके 20 में से 11 कैंडिडेट, यानी 37 परसेंट कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस हैं। इसके बाद कांग्रेस है, जिसके 99 में से 28 कैंडिडेट, यानी 28 परसेंट कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस हैं। असम गण परिषद के 26 में से छह कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस हैं और भाजपा के 9 परसेंट उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है। रायजोर दल के प्रेसिडेंट और सिबसागर से मौजूदा विधायक अखिल गोगोई पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस हैं। उनके चुनावी एफिडेविट से पता चलता है कि गोगोई पर 21 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं, जिनमें क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और जंग छेड़ने के लिए उकसाने जैसे गंभीर चार्ज शामिल हैं। उनके खिलाफ ज़्यादातर क्रिमिनल केस 2019 के एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में उनकी लीडरशिप से जुड़े हैं और उन्हें अभी तक इनमें से किसी भी केस में दोषी नहीं ठहराया गया है। आईयूडीएफ के फाउंडर और प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल ने कथित आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा एक क्रिमिनल केस पेंडिंग बताया है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के 2026 के चुनाव के लिए उनके नॉमिनेशन एफिडेविट के मुताबिक, उन पर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। होजाई से भाजपा के एक और उम्मीदवार शिलादित्य देव ने कथित तौर पर अपने खिलाफ करीब 13 क्रिमिनल केस बताए हैं।

असम चुनाव : चुनाव आयोग...

करने के लिए, आयोग ने असम सहित चुनाव वाले क्षेत्रों में हवाई दस्ते और निगरानी दल तैनात किए हैं। देशभर में 5,173 से अधिक हवाई दस्तों को 100 मिनट के भीतर शिकायतों का जवाब देने का काम सौंपा गया है, जबकि 5,200 से अधिक स्थैतिक निगरानी दल रणनीतिक स्थानों पर जांच कर रहे हैं और अचानक नाका लगा रहे हैं। आयोग ने मतदान वाले राज्यों में समन्वय और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस महानिदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें भी की हैं। इस बीच, कड़ी प्रवर्तन व्यवस्था के बीच, असम में चुनाव अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण रसद संबंधी उपलब्धि भी हासिल कर ली है, जिसमें सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की सेटिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को चालू कर दिया गया है। राज्य भर में मतदान की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अधिसूचित नामित केंद्रों पर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोगीकरण अभ्यास किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों ने मशीनों को कान्फिगर करने में सहायता की, जिससे सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई। कुल मिलाकर 41,320 बैलेट यूनिट (बीयू), 43,975 कंट्रोल यूनिट (सीयू) और 43,997 वीवीपीएटी मशीनें चालू कर दी गई हैं, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर 31,490 मतदान केंद्रों पर तैनात की जाने वाली आरक्षित इकाइयां भी शामिल हैं। रसद व्यवस्था और नियामक निगरानी दोनों को मजबूत किए जाने के साथ, राज्य मतदान से पहले तैयारियों के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है।

अफगानिस्तान में बारिश...

नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों ने बताया कि चार लोग अभी भी लापता हैं और कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। सड़कों के टूटने और रास्ते बंद होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही है, खासकर दूरदराज के इलाकों में। जाबिउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस आपदा में 3,000 से ज्यादा *जरीब* खेती की जमीन बर्बाद हो गई है और 1,000 से अधिक पशुधन की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। अफगानिस्तान में यह कोई नई समस्या नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में इस तरह की बाढ़ आती है और भारी नुकसान करती है। साल 2024 में भी ऐसी ही बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इससे पहले जनवरी में भी भारी बर्फबारी और बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घरों को नुकसान पहुंचा था।

एनडीए की 100 से ...

निभाया है। उनके जैसे नेताओं ने असम और भाजपा दोनों के लिए अमूल्य योगदान दिया है, और उनकी क्षमता या प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए सरकार के शासन रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि 2016 से उठाए गए निर्णायक कदमों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विकास को गति देने में मदद की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2016 से बदलाव देखा है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है, और यही कारण है कि पूरे असम में भारी समर्थन है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोनोवाल ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल के दौरान अवैध अप्रवासन को बढ़ावा दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान अवैध घुसपैठ की अनुमति दी गई और कई बांग्लादेशी असम में बस गए। इससे राज्य के लिए दीर्घकालिक चुनौतियां पैदा हुईं। उन्होंने आगे घोषणा की कि सरकार अतिक्रमित भूमि को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि आने वाले दिनों में, असम के संसाधनों और पहचान की रक्षा के हमारे प्रयासों के तहत लगभग पांच लाख बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। एनडीए के चुनावी प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए सोनोवाल ने व्यापक जनादेश की भविष्यवाणी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे असम में एनडीए एकजुट है, चाहे वह भाजपा हो, एजीपी हो या बीपीएफ। ऊपरी असम से लेकर निचले असम तक, हर क्षेत्र में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार जीत के लिए तैयार हैं। हमारा गठबंधन सौ से अधिक सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है।

जुबीन को जल्द मिलेगा ...

रूप से दूरी बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव के बाद गोमांस सेवन के मामले में कुंकी के माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा 90 से 100 सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जोरहाट की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पारदर्शी नियुक्तियों ने राज्य के युवाओं में आशा का संचार किया है और इसी कारण असम के युवा भाजपा के साथ खड़े हैं।

असम चुनाव से पहले ...

झुग्गियों में ज्यादातर लोग या तो असम की ट्रेन पकड़ चुके हैं या अगले दो दिन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि वोट डालना बहुत जरूरी है। दबी जुबान में यह भी कहते हैं कि उन्हें डर तो है ही। वैसे ही बांग्लादेशी करार दिया जाता है। वोट भी नहीं डालेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा परिवार समेत टिकट करवा लिया है और वोट डालने असम जा रहे हैं। इसी तरह से रेहाना खातून को लखनऊ में रहते एक दशक से ज्यादा हो गए। उनका कहना है कि इस बार डर के माहौल की वजह से भी लोग ज्यादा जा रहे हैं। लोगों के बीच ये बात फैली है कि वोट न डाला तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे। एसआईआर में वैसे ही बहुतों के नाम कटे हैं। इसी तरह से 22 साल से लखनऊ में रह रहे अब्दुल अली परिवार समेत कल असम की ट्रेन पकड़ने वाले हैं। वोट करने जा रहे हैं।

अगर नोटा जीत जाए...

मजबूर करना है। सिंबल के रूप में बैलेट पेपर पर एक काला क्रॉस होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर नोटा जीत जाता है, तो चुनाव कैंसिल हो जाता है, लेकिन मौजूदा कानूनी ढांचे के हिसाब से मामला थोड़ा अलग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के हिसाब से काल्पनिक जीत बनाम असली जीत: अभी, भारत में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता है। कानून: अगर नोटा को 1 लाख वोट मिलते हैं और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को 50,000 वोट मिलते हैं, तो 50,000 वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा क्यों है? कानून कहता है कि नोटा आपकी या मेरी तरह कोई व्यक्ति नहीं है। यह सिर्फ एक वोटिंग ऑप्शन है। इसलिए, जो उम्मीदवार वैलिड वोटों के मामले में उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट पाएगा, वही एमएलए बनेगा। तो नोटा पर वोट करने का क्या फायदा है? यहीं पर पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) केस का कॉन्टेक्स्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नोटा वोटर्स की भावनाओं को जाहिर करने का एक जरिया है। हालांकि, हाल के सालों में, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोकल इलेक्शन (पंचायत या म्युनिसिपैलिटी) में नियम बदले हैं। वहां, अगर नोटा जीतता है, तो दोबारा चुनाव का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन असेंबली या लोकसभा इलेक्शन के मामले में, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अभी भी पुराने नियमों को मानता है—यानी, अगर नोटा जीत भी जाता है, तो दूसरे नंबर पर आने वाला जीत जाता है। पश्चिम बंगाल के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर नोटा सिंबॉलिक तौर पर जीत भी जाता है, तो इसका सरकार बनाने या कैंडिडेट चुनने पर सीधा असर नहीं पड़ता है। हालांकि, यह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक कड़ा मैसेज है। आपका वोट आपका अधिकार है, इसलिए सोच-समझकर वोट करें।

व्हाइट हाउस के पास ...

ने पार्क और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से जुड़ी जानकारी या वीडियो फुटेज है, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान एक संभावित वाहन और एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के आसपास हाई अलर्ट घोषित कर दिया और कई सड़कों जैसे एच स्ट्रीट एनडब्ल्यू, आई स्ट्रीट एनडब्ल्यू और 16वीं स्ट्रीट एनडब्ल्यू को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस घटना का व्हाइट हाउस के नियमित कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है और वहां की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था, चारों तरफ फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे रही थीं और अधिकारी हर संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रहे थे। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में भी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को लेकर कितनी सतर्क रहती हैं।

चुनाव से पहले 650 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती

गुवाहाटी (हिंस)। चुनाव आयोग ने सामान्य चुनाव और उप-चुनाव 2026 के मद्देनजर की गई कार्रवाई में जब्त की गई सामग्रियों का कुल मूल्य 650 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी का संकेत है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आयोग ने प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं। इन बैठकों में हिंसा, भय और प्रलोभन से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निगरानी को मजबूत करने के लिए 5,173 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जो 100 मिनट के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर अचानक जांच के लिए 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं। आयोग ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली शुरू होने के बाद से 5 अप्रैल 2026 तक कुल 651.51 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। इसमें असम में 97 करोड़ रुपए की जब्ती दर्ज की गई। कुल जब्ती में 53.2 करोड़ रुपए नकद, 79.3 करोड़ रुपए की शराब, 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ, 58 करोड़ रुपए के बहुमूल्य धातु और 231.01 करोड़ रुपए के फ्री उपहार एवं अन्य सामग्री शामिल हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाशी और जांच के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां भी गठित की गई हैं। आयोग ने कहा कि नागरिक और राजनीतिक दल ईसीआईईटी के सी-विजिल मॉड्यूल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ओवैसी के असम दौरे का विरोध, नेतृत्व बदलाव की खबरों को बताया फर्जी

गुवाहाटी (हिंस)। ताई अहोम युवा परिषद, असम ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के असम दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन ने बीती रात ओवैसी को असम आने का निमंत्रण देने वालों की भी कड़ी आलोचना की। परिषद ने आरोप लगाया कि इस तरह के कदम राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं और साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। संगठन ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ओवैसी को असम की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। संगठन ने कहा कि ओवैसी शायद इस बात को भूल रहे हैं क्या अहोम ने किस तरह मुगलों को असम में प्रवेश करने से रोका था। इस बीच, परिषद ने अपने अध्यक्ष दिगंत तामुली को पद से हटाए जाने संबंधी खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। संगठन ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों में प्रकाशित यह खबर पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। संगठन के संयुक्त सचिव दीपज्योति बरुवा ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से इस तरह की फर्जी खबरें फैलायी जा रही हैं। उन्होंने मीडिया से खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की।

अभयापुरी के विकास के लिए मुख्यमंत्री हिमंत का 200 करोड़ रुपए का वादा

बंगाईगांव (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को अभयापुरी में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में यह दिखाना होगा कि असमिया लोग भी वोट देना जानते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल एक विशेष समुदाय ही संगठित तरीके से मतदान करता है, लेकिन इस बार अन्य लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे। भाजपा उम्मीदवार भूपेन राय के समर्थन में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री ने लोगों से निर्णायक मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के माध्यम से जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभयापुरी के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने *आत्मनिर्भर असम* अभियान के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सभा में भारी जनसमागम देखा गया। इस दौरान एक दिलचस्प क्षण भी सामने आया, जब एक युवक ने अपने सीने पर मुख्यमंत्री की तस्वीर बनाई थी। मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत करते हुए उसके प्रति स्नेह व्यक्त किया और उसे भविष्य में अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया।

प्रियंका गांधी के असम दौरे के साथ ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई : मंत्री शिवराज सिंह चौहान

गुवाहाटी (हिंस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को असम की बोकाखात और नाडुआर विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बोकाखात में बिहरा टी एस्टेट मैदान में असम गण परिषद (एजीपी) नेता अतुल बोरा और नाडुआर में भाजपा उम्मीदवार पद्म हजारिका के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि असम के लोग सरल, देशभक्त और ईमानदार हैं तथा राज्य की चाय विश्वभर में प्रसिद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो चुकी है और पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका

गांधी के असम दौरे के साथ ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि राज्य में *मामा हिमंत* की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस चिंतित है। कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने असम के साथ *पांच महापाप* किए। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय असम को पाकिस्तान में शामिल करने की बात, 1962 के युद्ध में राज्य को असहाय छोड़ना, बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देना, युवाओं को रोजगार न देना और परिवारवाद को बढ़ावा देना - ये कांग्रेस की बड़ी गलतियां रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजग सरकार राज्य में पांच वर्षों में दो लाख सरकारी नौकरियां देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी कहा कि असम में *लैंड जिहाद* और *लव जिहाद* को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा अवैध कब्जों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को अवसर दिया जाएगा। उन्होंने अरुणोदय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंची है। चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे पर बोलते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने उन्हें वर्षों तक जमीन का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से अब श्रमिकों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभा के अंत में चौहान ने असमिया में *जय आई असम, कांग्रेस खत्म* का नारा देते हुए दावा किया कि राज्य में एक बार फिर भाजपा-राजग की जीत सुनिश्चित है और जनता से गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

भूपेन बोरा का गौरव गोगोई पर तीखा हमला

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा भाजपा उम्मीदवार भूपेन बोरा ने चुनावी प्रचार के बीच कांग्रेस सांसद एवं असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर तीखा हमला बोला और उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाया। रविवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोरा ने कहा कि बड़ा असम बनाने की बात करने से पहले गौरव गोगोई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खुद चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई का असम की मिट्टी, पानी और वातावरण से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं है। बोरा ने यह भी कहा कि गौरव गोगोई को असम के राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय भावना को समझने में अभी 15 साल और लगेंगे। उनके इस बयान से चुनावी माहौल में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है।

नगांव में सूदखोरों और ड्रग तस्करों पर सख्ती का वादा, कांग्रेस पर पीयूष का निशाना

नगांव (हिंस)। असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने सूदखोरों और ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और लोगों से सही निर्णय लेने की अपील की। मंत्री पीयूष हजारिका नगांव में बीती रात एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके पहले नगांव के उरियागांव स्थित भूपेन हजारिका रंगमंच में आयोजित सभा में उन्होंने नगांव-बटद्रवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रूपक शर्मा के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जिले में सूदखोरी और नशे के कारोबार से जुड़े तत्वों को दोबारा सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हजारिका ने कहा कि पार्टी के 24 सीटें जीतने के दावे पर भी उन्हें संदेह है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रहा से भाजपा प्रत्याशी शशिकांत दास की जीत तय है और मध्य असम की सभी सीटें गठबंधन के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता हिमंत विश्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और उनके नेतृत्व में सरकार दोबारा बनेगी। रहा के चापरमुख में आयोजित एक अन्य सभा में हजारिका ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर अगले पांच वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर असम को बाढ़मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने रहा क्षेत्र में सभी तटबंधों के निर्माण का भी आश्वासन दिया और

कहा कि अगले वर्ष से सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो अरुणोदय जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए कांग्रेस को दिया गया वोट व्यर्थ जाएगा। करीब 10 हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में विभिन्न दलों के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद मंत्री ने दक्षिणपाट में भी एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित किया।

फकीराग्राम में टीएमसी के पक्ष में प्रचार जनता बदलाव के लिए तैयार-कीर्तिवर्धन झा

कोकराझाड़ (हिंस)। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के दौरान 4 नं. बाओखुंगुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फकीराग्राम में आयोजित आज जनसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता, सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर किर्तिवर्धन झा ने पार्टी की चुनावी रणनीति और एजेंडे को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी असम में विकास, शांति और सामाजिक समरसता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में वर्तमान सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करने में विफल रही है, जिसके कारण आम जनता बदलाव चाहती है। टीएमसी के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, किसानों को आर्थिक सहायता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि टीएमसी की नीतियां राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। झा ने बाओखुंगुरीर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार उदंगश्री नार्जारी के समर्थन में जनता से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि क्षेत्र में विकास की नई धारा बहाई जा सके। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई, जिससे टीएमसी के प्रति जनता के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि आगामी चुनाव में टीएमसी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी।

लोक भवन, असम ने *राजस्थान दिवस* मनाया

गुवाहाटी। लोक भवन, असम ने राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के मार्गदर्शन में, आज यहां *प्राग्ज्योतिष आईटीए सांस्कृतिक केंद्र* में आयोजित एक समारोह में, राजस्थान का *राज्य स्थापना दिवस* बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया। भारत सरकार की पहल *एक भारत श्रेष्ठ भारत* के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में राज्यपाल ने कहा कि इसका उद्देश्य हमारे राष्ट्र की *विविधता में एकता* की भावना को सुदृढ़ करना है, जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। राजस्थान की गौरवशाली विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस राज्य का गठन सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में विभिन्न रियासतों के एकीकरण के माध्यम से हुआ था। उन्होंने महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, मीराबाई और पन्ना धाय जैसी महान विभूतियों द्वारा प्रदर्शित साहस, बलिदान और समर्पण के मूल्यों को रेखांकित किया, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। राज्यपाल ने राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने *हवा महल* तथा जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भव्य किलों जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत और वैश्विक पर्यटन आकर्षण के चिरस्थायी प्रतीक बताया। असम और राजस्थान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद, दोनों राज्य एक साझा सांस्कृतिक लोकाचार के सूत्र में बंधे हुए हैं। राज्यपाल ने असम के प्रख्यात साहित्यकार, संगीतकार और स्वतंत्रता

सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाल का भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनकी पैतृक जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई हैं; यह तथ्य दोनों राज्यों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जीवन और उनके कार्य सांस्कृतिक एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रतीक हैं, और वे *एक भारत श्रेष्ठ भारत* पहल में निहित आदर्शों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल ने असम में रहने वाले राजस्थानी समुदाय द्वारा राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक संवर्धन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप, राज्य की सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति में सक्रिय रूप से अपना योगदान दें। इससे पूर्व, राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव श्री एसएस मीनाक्षी सुंदरम ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर *राजस्थान फाउंडेशन* के अध्यक्ष कैलाश काबरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर असम की प्रथम महिला श्रीमती कुमुद देवी, असम सरकार के प्रधान सचिव मुकेश चंद्र साहू, सुरेंद्र कुमार, फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी शंकर लाल गोयनका, कनोई कॉलेज, डिब्रूगढ़ के ट्रस्टी ज्योति प्रसाद कनोई और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

महानगर स्थित रबर का गोदाम जलकर राख, भारी नुकसान

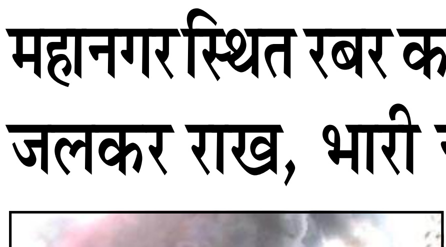

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी गुवाहाटी के वशिष्ठ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह अचानक लगी आग में पूरे इलाके में अपरातफरी फैल गयी। हादसे के दौरान दो गैस सिलिंडरों में भयानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग और तेजी से फैल गयी। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार वशिष्ठ के पाटरकुची के सात नंबर गली में स्थित रबर की गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गयी। रबर में लगी आग काफी तेजी से फैली, पूरे इलाके में काले धुंए का गुब्बार छा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के दौरान संभवत: गोदाम में रखे गैस सिलिंडरों में भयावह विस्फोट हुआ। बताया गया कि एक के बाद एक दो सिलिंडरों में विस्फोट हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस एवं अग्निशमन की लगभग पांच गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गयी। रबर का गोदाम कैप्टन नामक व्यक्ति का बताया गया है। आग बुझाने में अग्निशमन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में 50 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान जताया गया है। हालांकि, आग कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बाओखुंगुरी में त्रिकोणीय महामुकाबला : अनुभवी राजीव युवा रुपम और लोकप्रिय प्रतिभा के बीच दिलचस्प जंग

कोकराझाड़ (विभास)। असम में चुनावी बिगुल बजते ही 4 नंबर बाओखुंगुरी ओपन विधानसभा समष्टि में राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस बार यहां का चुनावी रणक्षेत्र किसी महासंग्राम से कम नहीं है, जहां निर्दलीय उम्मीदवार राजीव ब्रह्म, बीपीएफ के रुपम चंद्र राय और यूपीपीएल की प्रतिभा ब्रह्म के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस सीट पर हार-जीत का फैसला *आधी आबादी* के हाथ में है। कुल 1,66,279 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में 83,454 महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 82,824 है। माना जा रहा है कि जिस भी प्रत्याशी को महिलाओं का *मौन समर्थन* मिलेगा, विधानसभा की राह उसी के लिए आसान होगी। बीटीसी के बनारगांव से दो बार एमसीएलए और कार्यकारी सदस्य रह चुके राजीव ब्रह्म के पास लंबा अनुभव है। उनके पक्ष में बोड़ो, अल्पसंख्यक, बंगाली, आदिवासी और गोरखा सहित विभिन्न समुदायों का जनसैलाब उमड़ रहा है। उनकी जमीनी पकड़ अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीपीएफ ने युवा चेहरे रुपम चंद्र राय पर दांव खेला है। उन्हें राजवंशी समुदाय का मजबूत समर्थन

हासिल है। हालांकि, बाहरी होने का टैग (बंगाईगांव निवासी) और एनआरसी के समय के पुराने विवाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जिसे विपक्षी दल हथियार बना रहे हैं। यूपीपीएल की उम्मीदवार प्रतिभा ब्रह्म आम बोड़ो मतदाताओं और विशेषकर महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उन्हें कई अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों जैसे सुजीत दास और प्रणब बरुवा का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई है। हालिया परिसीमन ने बाओखुंगरी का भूगोल बदल दिया है। अब इसमें दोतामा, फकीराग्राम, बनारगांव और गुमा प्रर्बतझोरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां वर्तमान में बीपीएफ के प्रतिनिधियों का दबदबा है। यह आधार रुपम चंद्र राय के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले के अलावा मैदान में 12 अन्य प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। इसमें कांग्रेस की सेफली मार्क, टीएमसी की उदानश्री नार्जारी और निर्दलीय रंजीत सरकार व पृथ्वीराज नारायण देब प्रमुख हैं। अब देखना यह होगा कि बाओखुंगरी की जनता राजीव ब्रह्म के अनुभव पर भरोसा जताती है, रुपम राय के जरिए बीपीएफ की वापसी कराती है या प्रतिभा ब्रह्म को चुनकर नया जनादेश देती है।

असम में भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या चुनावी हिंसा का आरोप

चराईदेव (हिंस)। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हिंसा की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में चराईदेव जिले से एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि मृतक की पहचान खूदकन बोरा के रूप में हुई है, जो चुनाव प्रचार में जुटे थे। आरोप है कि जय भारत पार्टी के समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार, जय भारत पार्टी के समर्थक तिलेश्वर मुर्मू पर इस हत्या को अंजाम देने का आरोप लगा है। घटना के बाद सोनारी विधानसभा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोनारी के विधायक धर्मेश्वर कोंवर ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को रास्ते में रोककर पीट-पीटकर हत्या अस्वीकार्य है। क्षेत्र के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। चुनाव के मद्देनजर कड़ी पुलिस निगरानी के बावजूद इस तरह की घटना से लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं स्थानीय लोगों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

संपादकीय

बंगाल में अराजकता

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दर्शाने वाला है। बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और समय रहते कार्रवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा जा सकता है। जब राज्य में एसआईआर काम में लगे लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोगों में उपजे अविश्वास के मद्देनजर इस दिशा में सतर्क पहल जरूरी थी। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर विदेशियों की घुसपैठ की समस्या रही है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया द्वारा मतदाताओं की पड़ताल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते व जरूरी कागजों के उपलब्ध न होने से कुछ वैध मतदाताओं को अपनी वैधता की पुष्टि के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं को भी समझने की जरूरत है। ऐसे मतदाताओं के अविश्वास को भी दूर करने की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर शुरू से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडंबना है कि उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र को लोगों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि राज्य के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के बजाय मतदाताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये प्रेरित करेंगे। राज्य में स्वतंत्र-निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनेताओं को संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

> पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है।

न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा बल्कि नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा

दंड से सुधार की ओर विश्वास आधारित न्यायिक यात्रा

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था, अनुशासन, सुधार और विश्वास का वातावरण बनाना भी होता है। इसी दृष्टि से भारत सरकार द्वारा लाया गया जन विश्वास विधेयक 2026 पहले लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित होने से इसके कानून के रूप में अमल का रास्ता साफ हो गया। इसके माध्यम से उस व्यवस्था को विदा देने का जतन किया गया है, जिसमें छोटी-छोटी गलतियों या सामान्य नियम-कानूनों के उल्लंघन पर जेल की सजा का प्रावधान था, अब ऐसा होने पर आर्थिक दंड लगेगा। निश्चित ही इस विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, भारतीय कानूनी परिवेश की एक उजली भोर है। निश्चित तौर यह कानून दंडात्मक व्यवस्था से सुधारात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसमें लगभग 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर 784 प्रविधानों में संशोधन किये गये हैं और 700 से अधिक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ और न्यायिक तंत्र पर दबाव कम होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर भी वह 30 दिन तक वैध रहेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने पर सजा के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी तरह अन्य अनेक मामलों में ऐसा होगा। इनमें से कई मामले कारोबारियों से भी जुड़े हैं, जैसे पहले ड्रग्स एवं कास्मेटिक नियमों के उल्लंघन पर जेल हो सकती थी, लेकिन अब केवल जुर्माना लगेगा। जो छोटे कारोबारी प्रायः जटिल नियम-कानूनों के अनचाहे उल्लंघन के कारण दंडित होने के दबाव में भयभीत रहते थे, वे अब भयमुक्त होंगे।

> निश्चित ही इस विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, भारतीय कानूनी परिवेश की एक उजली भोर है। निश्चित तौर यह कानून दंडात्मक व्यवस्था से सुधारात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसमें लगभग 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर 784 प्रविधानों में संशोधन किये गये हैं और 700 से अधिक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ और न्यायिक तंत्र पर दबाव कम होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर भी वह 30 दिन तक वैध रहेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने पर सजा के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी तरह अन्य अनेक मामलों में ऐसा होगा। इनमें से कई मामले कारोबारियों से भी जुड़े हैं, जैसे पहले ड्रग्स एवं कास्मेटिक नियमों के उल्लंघन पर जेल हो सकती थी, लेकिन अब केवल जुर्माना लगेगा।

भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है भारत की व्यवस्था एवं कानूनों का सरल एवं सुगम बनाना, यह कानून उसी दिशा में एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपक्रम है। इस विधेयक से न केवल न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा बल्कि नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इसे न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की अवधारणा को व्यवहार में उतारने वाला कानून भी कहा जा सकता है। दंड नहीं, सुधार की भावना को बल देते हुए इस कानून से आम-जनता को कानून की जटिल प्रक्रियाओं एवं भ्रष्टाचार की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। भारतीय न्याय व्यवस्था लंबे समय तक दंड आधारित रही है, जिसमें छोटे-छोटे उल्लंघनों के लिए भी आपराधिक मुकदमे चल जाते थे। इससे अदालतों में मुकदमों का ढेर लग जाता था और आम नागरिक अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ जाते थे। जन विश्वास विधेयक ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है। इससे कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना और व्यवस्था बनाए रखना होगा। अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड तय करना न्याय के मूल सिद्धांतों के अधिक अनुरूप है।

इस कानून से न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और गंभीर अपराधों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। यह कानून न्यायिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे न्यायालयों का समय और संसाधन बचेंगे और न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी। इस कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यापार और उद्योग जगत में विश्वास का वातावरण बनाना भी है। पहले कई छोटे नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते थे, जिससे उद्यमियों और निवेशकों में भय का वातावरण रहता था। अब आर्थिक दंड के प्रावधान से अनुपालन का बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी होगी। इससे छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत में निवेश का वातावरण और बेहतर बनेगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि एक सरल और निवेश अनुकूल देश के रूप में मजबूत होगी।

इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी भावना भारतीय संस्कृति के बहुत निकट दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति में दंड से अधिक सुधार, प्रतिशोध से अधिक क्षमा और अपराध से अधिक परिमार्जन की परंपरा रही है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुधार का अवसर मिलना चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड देना न्याय नहीं, बल्कि अन्याय की श्रेणी में आ सकता है। इस दृष्टि से यदि कानून व्यवस्था में क्षमा, सुधार और परिमार्जन की व्यवस्था हो, तो समाज अधिक मानवीय और संवेदनशील बन सकता है। भारत की संस्कृति दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक और समन्वयवादी रही है। जन विश्वास विधेयक इसी भावना को आधुनिक कानूनी व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास प्रतीत होता है। यह कानून विश्वास आधारित शासन की ओर अग्रसर होने के साथ मेरा भारत महान्‌ का उद्घोष है। यह कानून सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने वाला भी है। जब सरकार नागरिकों को अपराधी मानने की बजाय जिम्मेदार नागरिक मानकर कानून बनाएगी, तो नागरिकों में भी कानून के प्रति सम्मान और पालन की भावना बढ़ेगी। विश्वास आधारित शासन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। भय आधारित शासन में नागरिक कानून से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलता है जबकि विश्वास आधारित शासन में नागरिक कानून का पालन स्वयं करते हैं। देश एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी का अहसास स्वतः जागता है।

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि न्यायिक, प्रशासनिक और कानूनी सुधार भी आवश्यक हैं। जन विश्वास विधेयक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। सरल कानून, कम सरकारी हस्तक्षेप, तेज न्याय प्रणाली और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण-ये सभी विकसित राष्ट्र की पहचान होते हैं। इस दृष्टि से यह कानून भारत को आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के बड़े कानूनी सुधार राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना संभव नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य शासन को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है, न्याय व्यवस्था को ज्यादा मानवीय एवं व्यावहारिक बनाना है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने इस विधेयक के पारित होने पर यह आशा व्यक्त की कि इसके जरिये भरोसे पर आधारित व्यवस्था का निर्माण होने के साथ आम नागरिक सशक्त बनेंगे। जन विश्वास विधेयक उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह दर्शाता है कि सरकार नागरिकों को दंडित करने की बजाय उनके साथ विश्वास का संबंध स्थापित करना चाहती है। यह कानून शासन और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाने का एक सराहनीय एवं सूझबूझभरा प्रयास है।

वास्तव में कानून का शासन ऐसा होना चाहिए, जिसमें मामूली गलती या किसी गफलत या अनजाने में की गई भूल कठोर सजा का कारण नहीं बननी चाहिए। अब जब जन विश्वास विधेयक से हालात में व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि इस विधेयक के प्रविधानों से आम जनता को अवगत कराया जाए, ताकि वह अधिकतम लाभ उठा सके और शोषण एवं भ्रष्टाचार से भी बच सके। ध्यान रहे आम लोग सशक्त तब होते हैं, जब वे नियम-कानूनों से भली तरह अवगत होते हैं। जनता को बदले हुए नियम-कानूनों से परिचित कराने का काम सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ उसे इसे लेकर सावधान रहना होगा कि छोटे अपराधों में जेल भेजने वाले प्रविधानों की जगह चेतावनी देने और जुर्माना लगाने वाली नई व्यवस्था से समाज में ऐसा कोई संदेश न जाए कि नियम-कानूनों के उल्लंघन पर जुर्माना देकर बचा जा सकता है। यदि जुर्माना देकर नियम-कानूनों को हल्के में लेने की प्रवृत्ति बढ़ी तो इस विधेयक का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जुर्माना लेने की परम्परा कहीं प्रशासनिक अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को अधिक भ्रष्ट न बना दे।

देश दुनीया से

नई सोच रोकेगी मनुष्यता के खिलाफ अपराध

स्वतंत्रता सेनानी और अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग के नेता बाबू जगजीवन राम को बचपन में स्कूल में इसलिए सज़ा मिली थी कि उन्होंने उस मटके से पानी पी लिया था जो स्कूल के सवर्ण अध्यापकों के लिए रखा गया था। यह बात तब की है जब हम गुलाम थे। पर ऐसे ही 'अपराध' के लिए स्वतंत्र भारत में भी नौ साल के एक दलित बच्चे को भी सजा मिली थी– राजस्थान के जालौर के एक स्कूल में उन बच्चों से भी अनजाने मे ही अध्यापकों के मटके से पानी पीने का 'अपराध' हो गया था। यह घटना हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह के दिन घटी थी। दोनों ही घटनाओं में लगभग एक सदी की दूरी है। सदियों से दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत में हमारी समाज व्यवस्था के माथे से यह कलंक मिट जायेगा। पर आज भी, यानी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में इस आशय के समाचार मिल जाते हैं कि फलां गांव में या फलां कस्बे में दलित समाज के किसी व्यक्ति को इसलिए सज़ा भुगतान पड़ी कि उसने घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनने का दुस्साहस किया था! आज़ादी प्राप्त करने के बाद जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की थी कि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक को अस्पृश्यता जैसे अभिशाप को झेलना न पड़े। एक लंबे संघर्ष के बाद यह स्थिति आयी थी, पर अभी भी अस्पृश्यता के अभिशाप से हम मुक्त नहीं हो पाये। सौ साल पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में अगड़ों के लिए आरक्षित समझे जाने वाले एक तालाब से पानी पीने के अधिकार का संघर्ष शुरू किया था। उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे, पर अस्पृश्य समझे जाने वाले दलित को यह अधिकार नहीं था। ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग यह मानते थे कि दलितों के छूने से वह भी अपवित्र हो जायेंगे। पता नहीं यह धारणा कब से चली आ रही है, पर यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि हमारे देश में आज भी छुआछूत से हमारा पीछा नहीं छूट पाया। शहरी भारत में भले ही माथे पर यह कलंक न दिखता हो, पर ग्रामीण भारत आज भी जैसे इस त्रास को भोगने के लिए शापित है। यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि लगभग अस्सी प्रतिशत भारत गांवों में बसता है! सन्‌ 1950 में हमने अपने संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की थी। हमारा संविधान कहता है, 'सरकार धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी'। लगता है, भेदभाव करने वालों ने मान लिया है कि यह व्यवस्था सरकार के लिए है, समाज के लिए नहीं! सौ साल पहले डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को यह अहसास कराने की कोशिश की थी। सौ साल पहले 20 मार्च, 1927 को महाराष्ट्र के एक तालाब के पानी को न केवल दलितों ने छुआ, बल्कि उस तालाब का पानी पिया भी। वस्तुतः यह मनुष्यता की रक्षा के लिए किये जाने वाले एक संघर्ष की शुरुआत थी। यह सौवां वर्ष है इस संघर्ष का— और संघर्ष आज भी जारी है। हम इस बात पर तो गर्व कर सकते हैं कि सौ साल पहले ऐसा कोई संघर्ष प्रारंभ हुआ था, पर देखा जाये तो यह शर्म की ही बात है कि अब तक इस संघर्ष में पूरी विजय नहीं मिल पायी। पर इस असफलता से संघर्ष की महत्ता कम नहीं हो जाती। ज़रूरी है कि महाड में शुरू किये गये इस जल-सत्याग्रह की महत्ता को समझा जाये, इस संघर्ष को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाये। उस दिन अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग ढाई हजार दलितों ने महाड के चौदार तालाब के पवित्र समझे जाने वाले जल को अंजलि में भरकर एक नई आजादी के संघर्ष की शुरुआत की थी। यह संघर्ष इस सिद्धांत को स्वीकारने के लिए भी था कि जल, जंगल और हवा प्रकृति ने हर प्राणी के लिए दिये हैं, किसी जन्म या किसी धर्म के नाम पर इनका बंटवारा नहीं हो सकता। किसी भी आधार पर प्रकृति के इन अवदानों पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। पर इस बात को सवर्ण समझे जाने वाले समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। महाड सत्याग्रह से नाराज सवर्णों ने न केवल तालाब का 'शुद्धीकरण' किया, बल्कि सत्याग्रहियों को मारा-पीटा भी गया था। वे मामले को अदालत में भी लेकर पहुंचे। दस साल लगे न्यायालय को पानी पर सबके अधिकार का फैसला सुनाने में। और यह भी हकीकत है कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा तबका मन से यह मानने को तैयार नहीं है कि दलितों को अस्पृश्य मानना मनुष्यता के खिलाफ एक अपराध है। सदियों से चले आ रहे इस अपराध का प्रायश्चित होना ही चाहिए। यह अपराध-बोध ही समता के इस संघर्ष को किसी तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता है। महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती। इस मान्यता को मिलने का मतलब है इस सत्य को स्वीकार करना कि किसी भी आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई नहीं होनी चाहिए। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के चार स्तंभों पर एक मानवीय समाज की संरचना को आकार दिया गया है। अम्बेडकर ने जल-सत्याग्रह के माध्यम से समानता की लड़ाई को नया आयाम दिया था। चावदार तालाब के इस सत्याग्रह के तीन साल बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों की समानता की लड़ाई का एक और मोर्चा खोला था। यहां विवाद दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर था। गांधीजी इससे दो दशक पहले दलितों को यह अधिकार दिये जाने के संघर्ष को प्रारंभ कर चुके थे। इतिहास की इन सारी बातों को याद करने का एक अवसर है जल-सत्याग्रह का यह शताब्दी वर्ष। इसे याद करने का मतलब समानता की एक अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। यह बात समझना ज़रूरी है कि समानता की यह लड़ाई किसी कानून या किसी सरकार के सहारे नहीं जीती जा सकती। आवश्यकता एक सामाजिक आंदोलन को चलाने, उसे गति देने की है। अम्बेडकर का जल-सत्याग्रह या गांधी का नमक- सत्याग्रह या दलित के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए किया गया मानवीय समानता का संघर्ष कुल मिलाकर समानता की एक ऐसी लड़ाई है जिसके पूरा हुए बिना मनुष्यता की लड़ाई किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। डाक्टर अम्बेडकर को हम संविधान के प्रमुख शिल्पी की तरह याद करते हैं। इस याद करने को सार्थक बनाने का अर्थ आदमी और आदमी के बीच की खाई को पाटना है। तीन साल पहले जारी किये गये एक आंकड़े के अनुसार देश में दलितों पर अत्याचार की पांच घटनाएं रोज घट रही हैं। जालौर के नौ साल के इंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय इन्हीं पांच में से एक है। यह अन्याय खत्म होना ही चाहिए– तभी मनुष्यता जीतेगी।

कुछ अलग

समय की पाबंदी

बात साबरमती आश्रम में गांधी जी के प्रवास के दिनों की है। एक दिन एक गाँव के कुछ लोग बापू के पास आए और उनसे कहने लगे, बापू कल हमारे गाँव में एक सभा हो रही है, यदि आप समय निकाल कर जनता को देश की स्थिति व स्वाधीनता के प्रति कुछ शब्द कहें तो आपकी कृपा होगी। गांधी जी ने अपना कल का कार्यक्रम देखा और गाँव के लोगों के मुखिया से पूछा, सभा के कार्यक्रम का समय कब है? मुखिया ने कहा, हमने चार बजे निश्चित कर रखा है। गांधी जी ने आने की अपनी अनुमति दे दी। मुखिया बोला, बापू मैं गाड़ी से एक व्यक्ति को भेज दूँगा, जो आपको ले आएगा। आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। गांधी जी मुस्कराते हुए बोले, अच्छी बात है, कल निश्चित समय मैं तैयार रहूँगा। अगले दिन जब पौने चार बजे तक मुखिया का आदमी नहीं पहुँचा तो गांधी जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अगर मैं समय से नहीं पहुँचा तो लोग क्या कहेंगे। उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा। गांधी जी ने एक तरीका सोचा और उसी के अनुसार अमल किया। कुछ समय पश्चात मुखिया गांधी जी को लेने आश्रम पहुँचा तो गांधी जी को वहाँ नहीं पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन वह क्या कर सकते थे। मुखिया सभा स्थल पर पहुँचा तो उन्हें यह देख कर और अधिक आश्चर्य हुआ कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और सभी लोग तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं। भाषण के उपरांत मुखिया गांधी जी से मिला और उनसे पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था लेकिन आप वहाँ नहीं मिले फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? गांधी जी ने कहा, जब आप पौने चार बजे तक नहीं पहुँचे तो मुझे चिंता हुई कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है इसलिए मैंने साइकिल उठाई और तेज़ी से चलाते हुए यहाँ पहुँचा।

आप का नजरीया

कमजोर होता रुपया

पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से मजबूत मुद्रा भंडार होने के बावजूद रुपये पर दबाव होना, देश के सामने कई तरह मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत फिर 2013 जैसी स्थितियों से रूबरू है। लेकिन इस बार जहां मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति 2013 के मुकाबले मजबूत है। दरअसल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक डॉलर को मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रूपये जैसी दूसरी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही वजह है कि एशिया में बेहद कमजोर स्थिति वाली मुद्राओं में रुपये भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक हकीकत यह भी है कि ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। इसकी एक विसंगति यह भी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। जिसका प्रतिशत 85 फीसदी के करीब है। फलतः तेल कंपनियां अधिक डॉलर की मांग कर रही हैं,जिसका असर रूपये की सेहत पर भी पड़ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में रुपये के मूल्य में दस फीसदी गिरावट और डॉलर के मुकाबले उसका सर्वकालिक निम्न स्तर तक पहुचना हमारी गंभीर चिंता का विषय होना ही चाहिए।

> निश्चित रूप से मजबूत मुद्रा भंडार होने के बावजूद रुपये पर दबाव होना, देश के सामने कई तरह मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत फिर 2013 जैसी स्थितियों से रूबरू है। लेकिन इस बार जहां मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति 2013 के मुकाबले मजबूत है। दरअसल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक डॉलर को मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रूपये जैसी दूसरी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही वजह है कि एशिया में बेहद कमजोर स्थिति वाली मुद्राओं में रुपये भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक हकीकत यह भी है कि ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है।

आशंका जतायी जा रही है कि यदि ईरान व अमेरिका का युद्ध और लंबा खिंचता है तो रूपये के मूल्य में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, अपनी तरफ से देश के केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक व रणनीतिक उपायों से रुपये की गिरावट को थमाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसका सीमित प्रभाव ही रहा है। भले ही भारत के पास सात सौ अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार हो, लेकिन उसका भी सीमित उपयोग ही रुपये के संरक्षण में हो सकता है। हालांकि, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार है कि दस महीने के आयात को सहजता से संचालित किया जा सकता है। वास्तव में वैश्विक परिदृश्य में जारी उथल-पुथल से बाधित आर्थिकी और असुरक्षा के चलते डॉलर की बढ़ती मांग ने रूपये को कमजोर बनाया है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से ही रुपये का गिरना संभल सकता है। केंद्रीय बैंक तेल कंपनियों के डॉलर के अतिरिक्त दबाव को कम करने को कदम उठा सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तेल कंपनियों के लिये अलग डॉलर विंडो बनाये जाने से रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। हर दिन तेल कंपनियों को भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है। यही मांग बाजार में रुपये पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। रिपोर्ट में एक सुझाव है कि इन कंपनियों के लिए अलग डॉलर विंडो बनाई जाए। अगर ऐसा होता है, तो बाजार में डॉलर की असली मांग और सप्लाई साफ दिखेगी। इससे रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम भी हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि रुपये को 'शॉक एब्जॉर्बर' बनाकर हर दबाव को झेलने के लिये छोड़ देने की नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि इस दिशा में केंद्रीय बैंक को आक्रमक रणनीति अपनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपये को संबल देने में करना चाहिए। इसके जरिये टाले जा सकने वाली गिरावट रोकी जा सकती है। इसके लिये अर्थव्यवस्था में नकदी संतुलन भी जरूरी है। बाजार की स्थिरता के लिये ब्याज दरों का संतुलन भी लाभप्रद हो सकता है।

दृष्टि कोण

एलपीजी का विकल्प बन सकती है बायोगैस

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की क्रांति लाई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती आयात निर्भरता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाल के समय में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। अमेरिका—इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। निःसंदेह, यह स्थिति भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को टालना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है—पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और घरेलू रसोई तक प्रभावित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशें। इसी संदर्भ में बायोगैस एक मजबूत और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरती है। बायोगैस जैविक कचरे—जैसे गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कचरा आदि—से उत्पन्न गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में पशुधन और जैविक कचरे की उपलब्धता इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है। गांवों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट स्थापित कर स्थानीय स्तर पर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाया जा सकता है, जो एलपीजी और सीएनजी का प्रभावी विकल्प है। 'गोबर-धन योजना' और 'एसएटीएटी' जैसी योजनाएं बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं।

इनके माध्यम से किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस में बदलकर न केवल ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 28–31 मिलियन टन के आसपास है। भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 10–12 एमएमटी प्रति वर्ष है। यानी कुल मांग का केवल 35–40 प्रतिशत ही देश में बनता है। भारत को हर साल लगभग 18–22 एमएमटी एलपीजी आयात करनी पड़ती है। यानी 60–65 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भरता। भारत आधा से ज्यादा एलपीजी बाहर से खरीदता है। आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं। भारत में अभी लगभग 132 सीबीजी प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 920 टन प्रतिदिन है। यानी अभी बायोगैस का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। भारत 20 एमएमटी सीबीजी बना सकता है। कुल संभावित क्षमता कचरा, गोबर, अवशेष की। कुल क्षमता लगभग 60 एमएमटी तक मानी जाती है। इसका मतलब भारत अपनी पूरी एलपीजी जरूरत (30 एमएमटी) बायोगैस से पूरा कर सकता है। फिलहाल अभी लगभग 300 से अधिक नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत में 2030 तक बायोगैस उत्पादन 7 गुना तक बढ़ सकता है। बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी : केशव प्रसाद मौर्य

गाजियाबाद (हिंस)। सपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलितों का ही हुआ है। महर्षि कश्यप जयंती पर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। अब प्रदेश को दंगा मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ दुष्प्रचार से प्रभावित होकर सपा और कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले तो उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नौटंकी करती रहती है, हाल ही में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति जैसी मूर्ति की फोटो शेयर की, जिसे सैफई में लगाने की बात कही गई। लेकिन मैं अखिलेश यादव को कहना चाहता हूं कि सैफई में रामलला की मूर्ति लगाने से अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को माफी नहीं मिलेगी। रामभक्त कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए चार राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें मेरी जनता से अपील है और विश्वास है कि जो 2017 में हुआ है वह 2027 में होगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में *जल स्वावलंबी* बन रहा राजस्थान

जयपुर (हिंस)। भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कम वर्षा, अनियमित मॉनसून, भूजल के अत्यधिक दोहन और मरुस्थलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण जल संसाधनों की कम उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में वर्षा के जल को व्यर्थ नहीं बहने देना और उसे भविष्य के लिए सहेजना ही एकमात्र उपाय है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुनर्जीवित कर चलाए जा रहे *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0* के जरिए हजारों गांवों के लाखों परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य जल संकट से प्रभावित सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर कर *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0* से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का समग्र मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्षा जल के अधिकतम संचयन के लिए एनिकट, चेक डैम, तालाब एवं जोहड़ का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पुराने जल स्रोतों की मरम्मत कर पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं भूजल स्तर में सुधार के लिए कुएं बनाए जा रहे हैं और सूखे बोरवेल को रिचार्ज पिट में बदला जा रहा है। इसी का परिणाम है कि कई स्थानों पर भूजल स्तर में सुधार हुआ है और गांवों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ने लगी है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता और हरित आवरण में वृद्धि, मिट्टी का कटाव कम होने और जैव विविधता में सुधार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ रहे हैं। बजट 2024-25 में घोषित इस अभियान के लिए कुल 11 हजार 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जिससे 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के पहले चरण में 349 पंचायत समितियों के 5 हजार 135 गांवों में कार्य करवाए गए। वहीं 1 लाख 10 हजार से अधिक कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 16 हजार से अधिक कार्य किए जा चुके हैं। जिन पर 2 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में 337 पंचायत समितियों में एक लाख से अधिक कार्य करवाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरुद्ध 2 हजार 880 करोड़ रुपए के 1 लाख 4 हजार से अधिक कार्यों का अनुमोदन किया जा चुका है। इनमें से 1 हजार 48 करोड़ से अधिक के 45 हजार से ज्यादा कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। इस चरण में अब तक 148 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय कर 8 हजार से ज्यादा कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्यों पर तेजी से काम जारी है। वहीं, बजट 2026-27 में इस अभियान के तृतीय चरण के तहत 2 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 हजार गांवों में 1 लाख 10 हजार कार्य करवाने की घोषणा की गई है। जनकल्याण के लिए चलाए जा रहे *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0* में जनभागीदारी के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका तय की गई है। कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। स्वयंसेवी संगठनों के साथ सीएसआर के तहत निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, जिससे सरकारी खर्च में भी कमी आई है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे जीआईएस आधारित मैपिंग, ड्रोन सर्वे, जल संरचनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सतत निगरानी सुनिश्चित हुई है। वहीं, इस अभियान के जल जीवन मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि जैसी अन्य योजनाओं से समन्वय के कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग और व्यापक प्रभाव सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0* एक दूरदर्शी और प्रभावी पहल है, जिससे जल संकट का धीरे-धीरे समाधान हो रहा है।

बीकानेर में वायरल ऑडियो-वीडियो पर सियासत गरमाई

गोविन्दराम मेघवाल की रैली में शक्ति प्रदर्शन

बीकानेर (हिंस)। जिले में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री से जुड़े कथित ऑडियो-वीडियो वायरल होने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। मामले को लेकर जहां यूथ कांग्रेस के देहात अध्यक्ष भंवर कूकणा और शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल ने विरोध जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया, वहीं पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल ने भी रविवार को रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। कर्मचारी मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए गोविन्दराम मेघवाल ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी दल या उनके अपने ही क्यों न हों। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। मेघवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के पुत्र रविशेखर के इशारे पर यह ऑडियो तैयार कर वायरल किया गया, जिससे उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कुछ नेता भी इस साजिश में शामिल होकर उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षित सीटों पर टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि मजबूत उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने पर समझौता संभव नहीं होगा। रैली के बाद गोविन्दराम मेघवाल अपने समर्थकों के साथ कर्मचारी मैदान से अंबेडकर सर्किल तक जुलूस निकालते हुए पहुंचे और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पंचायत समिति के पूर्व प्रधान लालचंद आसोपा, सरिता चौहान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशिकला राठौड़, आजम अली, शब्बीर अहमद सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग मौजूद रहे।

शिकार करने पहुंची लेपर्ड पर कुत्ता पड़ा भारी, जान बचाकर भागी

पाली (हिंस)। जिले के बाली क्षेत्र स्थित जवाई लेपर्ड इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शिकार करने पहुंची मादा लेपर्ड को कुत्ते के सामने उल्टे पांव भागना पड़ा। यह पूरा घटनाक्रम चार अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। हिल रेस्ट एरिया में सुबह मादा लेपर्ड ने एक बकरे का शिकार किया था। शाम को जब वह अपने शिकार को लेने वापस लौटी, तब वहां तीन कुत्ते मौजूद थे। जैसे ही लेपर्ड ने मौका देखा, उसने झपट्टा मारकर एक कुत्ते को दबोच लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच जोरदार संघर्ष चला। लेपर्ड कुत्ते को मुंह से पकड़कर घसीट रही थी, लेकिन तभी कुत्ते ने पलटवार करते हुए लेपर्ड को जमीन पर गिरा दिया। अचानक हुए इस पलटवार से घबराकर लेपर्ड ने शिकार छोड़ दिया और तेजी से जंगल की ओर भाग निकली। वन विभाग के अनुसार, वीडियो में दिख रही मादा लेपर्ड को स्थानीय स्तर पर एफ2 नाम दिया गया है। वह अपने पहले किए गए शिकार को लेने आई थी, लेकिन कुत्तों की मौजूदगी के कारण स्थिति बदल गई। गौरतलब है कि जवाई क्षेत्र देशभर में लेपर्ड की बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। यहां करीब 20 गांवों में 50 से अधिक लेपर्ड परिवार रहते हैं और इनका आवास अक्सर मानव बस्तियों के आसपास ही होता है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाएगी जनता : बड़ौली

महाराजा सूरजमल प्रतिमा अनावरण से राष्ट्रभक्ति संदेश सशक्त हुआ

सोनीपत (हिंस)। मोहन लाल बड़ौली ने सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया और युवाओं को राष्ट्रभक्ति, साहस तथा सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन करते हुए रविवार को मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि महाराजा सूरजमल युद्ध कौशल, रणनीति और वीरता के अद्वितीय प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कभी पराजय स्वीकार नहीं की। वे न्यायप्रिय, दूरदर्शी तथा किसानों के हितों के प्रति समर्पित शासक थे। उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देती रहेगी। पत्रकारों से बातचीत में मोहन लाल बड़ौली ने आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जनता के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में पार्टी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। किसान हितों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार मंडियों में बेहतर व्यवस्था लागू कर रही है, जिससे

किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। सरकार 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सोनीपत विधयक निखिल मदान और पूर्व मेयर राजीव जैन, जिला अध्यक्ष अशोक भरद्वाज, सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण और सामाजिक एकता के संकल्प के साथ हुआ।

भारत-पाकिस्तान सीमा के पास डेनमार्क का युवक गिरफतार, जांच एजेंसियां सक्रिय

बीकानेर (हिंस)। भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक खाजूवाला क्षेत्र में डेनमार्क के एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पकड़ा गया। वह करीब सात महीने पहले एक साल के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। पुलिस के अनुसार खाजूवाला बाजार के हॉस्पिटल रोड पर स्थानीय लोगों ने एक विदेशी युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा। सीमावर्ती क्षेत्र में आमतौर पर विदेशी नागरिकों की आवाजाही नहीं होने के कारण लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई किशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में युवक ने खुद को डेनमार्क का निवासी बताया और कुछ सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए, लेकिन बाद में वह चुप हो गया। थाने लाए जाने पर युवक भावुक हो गया और रोने लगा, जिससे मामला गंभीर हो गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी मौके पर बुलाया गया। संयुक्त रूप से पूछताछ के दौरान युवक के पास से कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन उसकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक के पास वैध पासपोर्ट और एक साल का वीजा है, हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश के

लिए आवश्यक विशेष अनुमति उसके पास नहीं थी। खाजूवाला क्षेत्र पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब होने के कारण यहां विदेशी नागरिकों की एंट्री प्रतिबंधित होती है। फिलहाल पुलिस ने युवक को आगे की गहन जांच के लिए बीकानेर स्थित जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर भेज दिया है, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे हर पहलू पर पूछताछ कर रही हैं। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि युवक जानकारी के अभाव में इस संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच गया, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

चकिया मदरसा में छापेमारी, विदेशी पिस्टल बरामद, तीन संदिग्ध हिरासत में

मदरसा किया गया सील

पूर्वी चंपारण (हिंस)। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिला पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा स्थित मदरसा में छापेमारी की है। उक्त कारवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार मदरसा से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार मदरसा परिसर से साजिश के कुछ सुराग मिले है, जिसको लेकर अग्रतर कारवाई जारी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तीन लोगों को भी हिरासत में लिया है और जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। फिलहाल मदरसा को सील कर दिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है, कि चकिया थाना क्षेत्र का यह वही मदरसा है, जहां से पहले पीएफआई से जुड़े सदस्य उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को चकिया पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। पीएफआई के सदस्य याकूब खान ने सोशल मीडिया में अयोध्या राममंदिर के विरोध में विवादित पोस्ट किया था। उसने अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने की बात सोशल मीडिया में कही थी। जिसके बाद उसे इसी मदरसा से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की जांच में यह सामने आया कि वह पीएफआई के स्लीपर सेल के लिए काम कर रहा था, साथ ही उसने पीएफआई के प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लिया था। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मदरसा की भूमिका की जांच कर रही है।

धर्म परिवर्तन करने वालों को बंद हो आरक्षण सुविधा : प्रवीण डोलके

वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में हरियाणा पहुंची पूर्वोत्तर की लड़कियां

पानीपत (हिंस)। पानीपत जीटी रोड स्थित एसडीवीएम स्कूल में वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर की लड़कियों का हरियाणा भ्रमण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर की लड़कियों को हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करना था, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय संपर्क कार्यकर्ता प्रशासनिक दिल्ली प्रवीण ढोलके ने कहा कि देश में धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण की सुविधा बंद करने पर विचार चल रहा है। जिसके समर्थन में पूरे भारत से वनवासी कल्याण आश्रम के दो लाख वनवासी 24 मई को लाल किला मैदान में एकत्र होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 1952 में हुई थी। और अब इस आश्रम से 12.5 करोड़ वनवासी बंधु जुड़ चुके है। उन्होंने बताया की 23 हजार सेवा प्रकल्पों द्वारा ढाई करोड़ वनवासी

बंधुओं को लाभान्वित किया गया है। जिस कारण वनवासी बंधु समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर राष्ट्र की सुरक्षा, एकता व अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि छात्रावास की 30 छात्राएं यहां की संस्कृति से रूबरू होने के लिए पानीपत में पहुंची, नगर के एक एक परिवार दो छात्राओं को अपने घर ले गए। परिवार में जाकर ये लड़कियां हरियाणवी संस्कृति को समझ सकेंगी व कल्याण आश्रम के छात्रावास में रहकर जो अनुशासन व संस्कार सीखे हैं, उनकी जानकारी परिवारों के साथ साझा करेंगी। उन्होंने जानकारी दी कि गैर वनवासी क्षेत्र हरियाणा में भिवानी व फरीदाबाद में दो छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर से छात्र आकर शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ हर वर्ष एक करोड़ रुपए केरल, उड़ीसा व झारखंड प्रांतों को आर्थिक सहयोग के रूप में भेजा जा रहा हे तथा शीतला माता मंदिर गुरुग्राम व मनसा देवी मंदिर पंचकूला से साड़ियां व लेडीज सूट प्राप्त कर देश के विभिन्न वनवासी क्षेत्रों में भेज जा रहे है। कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पालीवाल, मुख्य अतिथि धीरज मिगलानी, विशिष्ठ अतिथि पंकज गोयल, विशिष्ठ अतिथि अरुण कुमार फुटेला, मुख्यवक्ता प्रवीण डोलके ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जुगल किशोर ने आये हुए सभी अतिथियों एवं स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में विशेष रूप अनूप गर्ग, आर डी कल्याण, सुरेश गुप्ता, मुनेश्वर दयाल, प्रवीण कुमार, धीरज कपूर व बड़ी संख्या में नगर से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

खालसा साजना दिवस पर पाकिस्तान जाने वाले जत्थे के कार्यक्रम में बदलाव

अमृतसर (हिंस)। खालसा साजना दिवस के मौके पर पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन के लिए जाने वाले जत्थे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नण ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले जत्था 12 अप्रैल को रवाना होना था, लेकिन अब नए शेड्यूल के अनुसार श्रद्धालु 10 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और 19 अप्रैल को वापस लौटेंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए एसजीपीसी की ओर से 1860 पासपोर्ट भेजे गए हैं और करीब 1800 श्रद्धालुओं को वीजा मिला है। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए गुरुधामों के दर्शन के लिए संगत में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान अकेली महिलाओं के यात्रा पर जाने को लेकर लगाई जा रही पाबंदियों की खबरों को खारिज करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि एसजीपीसी द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फलका थाना उपद्रव मामले में पांच गिरफ्तार, पुलिस से हथियार छीनने का आरोप

कटिहार (हिंस)। जिले के फलका थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई घटना में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी हथियार छीनने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिवाकर कुमार यादव, मोनू यादव, प्रभात कुमार, रौशन कुमार और अभिमन्यु कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फलका थाना क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिवाकर कुमार यादव मुख्य आरोपी है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 1 मई से करेंगे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा

बरेली (हिंस)। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक और बयान से सियासी और धार्मिक माहौल को गरम हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गोहत्या रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में गोहत्या के मामले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। उन्होंने 1 मई से राज्य की हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने का एलान किया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तब लोगों को उम्मीद थी कि गोहत्या पर सख्ती से रोक लगेगी, लेकिन हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य ने दावा किया कि प्रदेश में बूचड़खाने सरकारी अनुमति और हस्ताक्षर के आधार पर संचालित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी बाजारों में गोमांस की खुलेआम बिक्री हो रही है, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि यदि सरकार ने गोवंश संरक्षण और गोहत्या रोकने का वादा किया था, तो फिर जमीन पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं और दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि संत समाज का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। संतों का काम समाज को दिशा देना और लोककल्याण के लिए आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं और कोई संन्यासी दोनों भूमिकाएं एक साथ नहीं निभा सकता। आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जनता को ऐसी सरकार चुननी चाहिए, जो गोहत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की इच्छाशक्ति रखती हो। उन्होंने सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों से इस मुद्दे पर सजग रहने की अपील की। उन्होंने ऐलान किया कि 1 मई से वह प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रदेश और धर्महित में कैसी सरकार जरूरी है। उनके मुताबिक यह अभियान राजनीतिक नहीं, बल्कि जनजागरण के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

हनुमान चालीसा पाठ से गूंजा श्री रामचंद्र जी मंदिर

जयपुर (हिंस)। चांदपोल स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। संत अमरनाथ महाराज के सानिध्य में श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति द्वारा *हर घर में हो अर्थ सहित हनुमान चालीसा* अभियान के तहत सैकड़ों श्रद्धालुओं को अर्थ सहित हनुमान चालीसा की पुस्तकें भेंट की गईं। इसका उद्देश्य भक्तों को पाठ के साथ उसके गूढ़ अर्थ से भी अवगत कराना है। समिति के अनुसार अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर लगातार हनुमान चालीसा का

वितरण कर रही हैं। इस पहल के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को धर्म, भक्ति और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को भन्दे बालाजी महाराज का सिंदूर लगाया गया, जिसे भक्तों ने आस्था के साथ ग्रहण किया। मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और सभी ने मिलकर भक्ति एवं एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में महेश बंब, सरदार राजन सिंह, रामस्वरूप यादव, अशोक कुमार विजयवर्गीय, पिंकी मुनीम, विजय, शैलेन्द्र यादव सहित अन्य श्रद्धालु एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

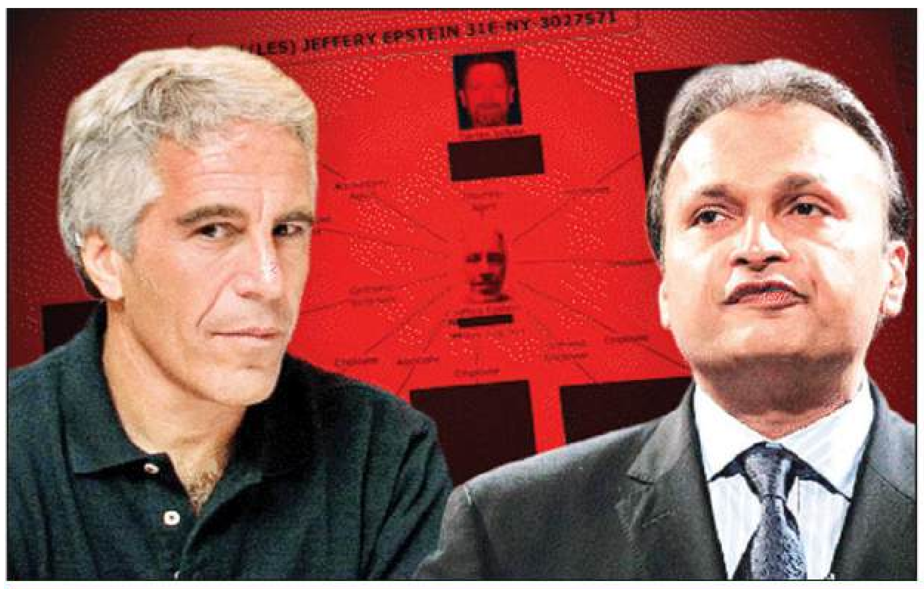

दावा-एपस्टीन और अनिल अंबानी के बीच सैकड़ों मैसेज-ईमेल हुए :यौन अपराधी ने खुद को व्हाइट हाउस का इनसाइडर बताया, नियुक्ति-विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां दीं

न्यूयार्क

अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन ने 2017 में उद्योगपति अनिल अंबानी के सामने खुद को डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के व्हाइट हाउस के इनसाइडर की तरह पेश किया था। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच दो साल तक सैकड़ों मैसेज और ईमेल हुए।

इनमें एपस्टीन ने ट्रम्प प्रशासन की नियुक्ति व विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां साझा कीं, जो बाद में सही भी निकलीं। हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि एपस्टीन की व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच थी।

मैसेज में अनिल अंबानी ने एपस्टीन को लिखा था- भारत के रिश्ते और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपकी गाइडेंस चाहिए। जवाब में एपस्टीन ने इनसाइड जानकारी देने का वादा किया।

सिग्नल-टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म पर होती थी बात - न्यूयार्क टाइम्स ने जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मैसेज के रीव्यू के आधार पर बताया कि अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच बातचीत सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म पर होती थी, जहां अंबानी अरमानी ए नाम से सक्रिय थे।

यह संपर्क उस दौर का है, जब एपस्टीन नाबालिगों से जुड़े अपराधों में जेल की सजा काट चुका था। इनका परिचय दुबई की कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलायेम ने कराया था। एपस्टीन ने जब दीपक चोपड़ा से अंबानी के बारे में राय मांगी, तो चोपड़ा ने उन्हें बेहद अमीर, चर्चा में रहने का शौकीन और सेलेब्स के प्रति सजग व्यक्ति बताया था।

सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति पर एपस्टीन की बात सच हुई - मैसेज में एपस्टीन खुद को असरदार पावर ब्रोकर के रूप में पेश करता दिखा। मार्च 2017 में अनिल अंबानी ने एपस्टीन से पूर्व सीआईए डायरेक्टर डेविड पेट्रेयस के भारत में अमेरिकी राजदूत बनने की संभावना पूछी थी। एपस्टीन ने जवाब दिया था- वे प्राथमिकता में नहीं हैं। बाद में केनेथ जस्टर राजदूत बने। जुलाई 2017 में एपस्टीन ने यह इनसाइड जानकारी भी दी कि जान बोल्टन नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। हालांकि, तब ट्रम्प ने मौजूदा मैकमास्टर का बचाव किया था। हालांकि, 8 महीने बाद एपस्टीन की बात सच साबित हुई और बोल्टन ने ही पद संभाला।

न्यूज ब्रीफ

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने की 2 लाख करोड़ की स्कीम तैयार

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी हालात को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है। संभावित आर्थिक असर से निपटने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। इस योजना का आकार करीब 2 लाख करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसे जल्द लागू किया जा सकता है। यह स्कीम कोविड-19 महामारी के दौरान लागू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के आधार पर तैयार की जा रही है। उस समय इस योजना ने कारोबारियों को वित्तीय संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई थी। नई योजना के तहत व्यवसायों को बिना किसी गिरवी के सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा। खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस स्कीम के मुख्य लाभार्थी होंगे, क्योंकि ये सेक्टर नकदी प्रवाह पर ज्यादा निर्भर रहता है और वैश्विक झटकों से जल्दी प्रभावित होता है। सरकार बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इससे छोटे और मध्यम कारोबारों को अपनी गतिविधियां जारी रखने में मदद मिलेगी और लिक्विडिटी की समस्या से राहत मिल सकेगी।

वीकेंड राइड के लिए 150-200सीसी बाइक्स बनीं पहली पसंद

नई दिल्ली। भारतीय युवाओं में वीकेंड राइड के लिए 150-200सीसी बाइक्स पहली पसंद बनी हुई है। युवाओं के रुझान को देखते हुए कंपनियां भी ऐसी ही बाइक्स का निर्माण कर रही है। बाइक निर्माता स्वदेशी कंपनी बजाज की बजाज पल्सर एनएस 200 बाइक अपनी पावर और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है। इसका 199.5 सीसी इंजन तेज पिकअप और दमदार परफार्मेंस देता है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए उपयुक्त है। वहीं टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी रेसिंग डीएनए और एडवांस फीचर्स के साथ आती है, जिसमें शार्प हैंडलिंग और राइडिंग मोड्स इसे खास बनाते हैं। अगर स्मूथ और रिफाइंड राइड चाहिए, तो होंडा हार्नेट 2.0 बेहतर विकल्प है, जो कम मेंटेनेंस और बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है। बजट और स्टाइल के संतुलन के लिए हीरो एक्सट्रीम 160आर अच्छा विकल्प है, जिसमें हल्का वजन और बढ़िया पिकअप मिलता है। वहीं यामाहा एफझेड-एक्स कम्फर्ट और स्मूथनेस के लिए पसंद की जाती है। शहर की ट्रैफिक भरी सड़कों पर आसान राइड और वीकेंड पर लंबी ड्राइव का मजा लेना हो, तो 150सीसी से 200सीसी सेगमेंट की बाइक्स सबसे संतुलित विकल्प बनकर उभरती हैं। इस सेगमेंट की मोटरसाइकिलें पावर, माइलेज, हैंडलिंग और कम्फर्ट का बेहतरीन संतुलन देती हैं, जिससे ये रोजमर्रा की जरूरतों के साथ एडवेंचर राइड के लिए भी उपयुक्त रहती हैं।

नया फ्लैगशिप स्कूटर सिंपल अल्ट्रा पेश, 400 किमी है रेंज

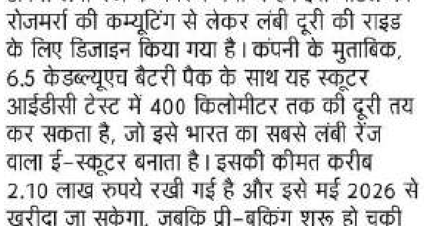

नई दिल्ली। सिंपल एनर्जी ने अपना नया फ्लैगशिप स्कूटर सिंपल अल्ट्रा पेश कर दिया है। यह स्कूटर अपनी लंबी रेंज के कारण चर्चा में है। इस माडल को रोजमर्रा की कम्यूटिंग से लेकर लंबी दूरी की राइड के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, 6.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ यह स्कूटर आईडीसी टेस्ट में 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो इसे भारत का सबसे लंबी रेंज वाला ई-स्कूटर बनाता है। इसकी कीमत करीब 2.10 लाख रुपये रखी गई है और इसे मई 2026 से खरीदा जा सकेगा, जबकि प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिजाइन के मामले में सिंपल अल्ट्रा स्पोर्टी और शार्प लुक के साथ आता है। इसमें एप्रन माउंटेड हेडलैंप, इंटीग्रेटेड क्ष्क्ष्ह्ह्य और स्लीक टेल सेक्शन दिया गया है। 780 मिमी सीट हाइट और 172 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। परफार्मेंस की बात करें तो इसमें 8.8 केडब्ल्यू की पीएमएसएम मोटर दी गई है, जो 72 एनएम टार्क जनरेट करती है।

सुजुकी बुर्जमान स्ट्रीट 125 का नया अपडेटेड माडल लान्च

नई दिल्ली

सुजुकी बुर्जमान स्ट्रीट 125 का नया अपडेटेड माडल भारत में लान्च हो गया है। 2026 अपडेट में कंपनी ने इसकी डिजाइन को और आकर्षक बनाया है, जिसमें नई एलईडी हेडलाइट्स, टेललाइट्स और रिवाइज्ड स्टाइलिंग शामिल है। यह माडल प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर स्टाइल और एडवांस फीचर्स के साथ आता है। यह स्कूटर खासतौर पर शहर की ट्रैफिक और फैमिली उपयोग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, साथ ही लंबी दूरी की सवारी के लिए भी आरामदायक माना जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में लगभग 1.02 लाख रुपये से शुरू होकर 1.13 लाख रुपये तक जाती है।

डिजाइन की बात करें तो नया बुर्गमेन स्ट्रीट 125 शार्प और एलिगेंट लुक के साथ पेश किया गया है। इसमें फ्लोइंग कर्व्स, क्रिस्प लाइन्स, बाडी-माउंटेड विंडस्क्रीन और अपस्वेप्ट मफलर जैसे एलिमेंट्स इसे प्रीमियम अपील देते हैं। 12-इंच रियर व्हील और चौड़ा स्टांस इसकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। इसकी सीट हाइट करीब 775-780 मिमी और ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिमी है, जिससे राइडिंग आसान हो जाती है। फीचर्स के मामले में यह स्कूटर काफी एडवांस है।

सेफ्टी के लिए सीबीएस और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 124सीसी का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.7 पीएस पावर और 10.2 एनएम टार्क जनरेट करता है। यह स्कूटर करीब 50 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट के साथ ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल या टीएफटी डिस्प्ले, काल और एसएमएस अलर्ट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और बड़ा अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है।

जिस अमेरिकी कंपनी ने कर्मचारियों को निकाला.......उसी पर ईरान ने दाग दी मिसाइल

दुबई। दुबई में अमेरिकी आईटी कंपनी ओरेकल कार्पोरेशन के दफ्तर पर ईरान द्वारा मिसाइल हमला किया गया। दुबई के अधिकारियों ने पुष्टि की कि दुबई इंटरनेट सिटी में ओरेकल की बिल्डिंग के सामने के हिस्से पर हवाई हमला हुआ। हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह हमला ईरान द्वारा किया गया माना जा रहा है, क्योंकि यूएई अमेरिका का सहयोगी देश है और वहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। दुबई मीडिया आफिस ने इस मिसाइल अटैक की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि दुबई इंटरनेट सिटी में ओरेकल बिल्डिंग के सामने के हिस्से पर हवाई हमला हुआ। इस बिल्डिंग के मलबे से हुई एक छोटी सी घटना घटी। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल, दुबई का कहना है कि यह ईरान ने ही ड्रोन-मिसाइल से अटैक किया है। बता दें कि यूएई खाड़ी में अमेरिका का सहयोगी देश है। यहां अमेरिकी सैन्य ठिकाना है। इसलिए ईरान दुबई पर बमबारी कर रहा है। हाल ही में ओरेकल ने वैश्विक स्तर पर करीब 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जिसमें से भारत में 12,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। छंटनी के कारण संगठनात्मक बदलाव और पद अप्रासंगिक होने की वजह से यह निर्णय लिया गया। प्रभावित कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया कि उन्हें सेवा-समाप्ति तक वेतन और बोनस, छुट्टियों का भुगतान, ग्रेच्युटी और नोटिस पीरियड का भुगतान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को दो महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ठहराव, निजी कंपनियों ने बढ़ाए दाम

नई दिल्ली

कच्चा तेल 100 डालर प्रति बैरल के पार

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों को पुराने स्तर पर बनाए रखा है, लेकिन निजी कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों को राहत देते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौजूदा समय में पेट्रोल की कीमतें लगभग 94 से 106 रुपये प्रति लीटर के बीच हैं, जबकि डीजल 78 से 97 रुपये प्रति लीटर के दायरे में बिक रहा है। हालांकि, निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल से एक प्रमुख निजी कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 7.41 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है, वहीं डीजल की कीमत में 25 रुपये तक का बड़ा इजाफा किया गया है। इसके बाद निजी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल करीब 119 रुपये और डीजल लगभग 123 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को मुख्य कारण माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल 100 डालर प्रति बैरल के पार चला गया है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ गई है। निजी कंपनियां इस बढ़ती लागत का असर सीधे ग्राहकों पर डाल रही हैं। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसकी कीमत 160 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। टाटा समूह से जुड़ी बड़ी खबर में वेनु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट के एक प्रमुख ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे। टाटा समूह के सात ट्रस्टों के वाइस चेयरमैन और टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन एमेरिटस वेनु श्रीनिवासन ने 4 अप्रैल को बाई हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट से ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। यह टाटा ट्रस्ट का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन ने अपने इस्तीफे के पीछे व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को कारण बताया है। हालांकि, उनका यह कदम ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही पूर्व ट्रस्टी मेहुल मिस्त्री ने उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। मिस्त्री ने दावा किया था कि श्रीनिवासन और विजय सिंह ट्रस्टी बनने के लिए निर्धारित योग्यता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था।

आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

सुझावों के लिए 30 अप्रैल तक का समय, राज्यों के दौरे से जुटाई जाएगी राय

नई दिल्ली

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। आठवां वेतन आयोन ने अपनी प्रक्रिया को तेज करते हुए सुझाव जुटाने और जमीनी स्तर पर बातचीत का दौर शुरू कर दिया है, जिससे जल्द सिफारिशें आने की उम्मीद बढ़ गई है। 3 नवंबर 2025 को गठित यह आयोग अब अपने काम के अहम चरण में पहुंच गया है। आयोग के पास रिपोर्ट सौंपने के लिए सीमित समय बचा है, ऐसे में प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। नोटिस के अनुसार, जो संगठन आयोग की विजिटिंग टीम से सीधे संवाद करना चाहते हैं, उन्हें 10 अप्रैल 2026 तक ईमेल के जरिए अपाइंटमेंट लेना होगा। इसके अलावा वेतन, भत्तों और पेंशन सुधार से जुड़े अपने सुझाव 30 अप्रैल 2026 तक भेजने होंगे इन सुझावों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे को प्रभावित करेंगी इसके साथ ही आयोग ने जमीनी फीडबैक लेने के लिए राज्यों के दौरे की भी योजना बनाई है। 30 मार्च को जारी जानकारी के अनुसार, टीम अपने दौरे की शुरुआत उत्तराखंड से करेगी। यहां विभिन्न संगठनों और संस्थानों से चर्चा कर उनकी राय ली जाएगी। बैठकों का समय और स्थान संबंधित पक्षों को ईमेल के जरिए बताया जाएगा। गौरतलब है कि सातवा वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उनकी आय में अच्छी बढ़ोतरी संभव है।

टाटा नेक्सन का जलवा बरकरार, - मार्च 2026 में बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कामैक्ट एसयूव्ही

नई दिल्ली

भारतीय आटो बाजार में टाटा नेक्सन की लोकप्रियता एक बार फिर साबित हो गई है। मार्च 2026 में यह देश की बेस्ट-सेलिंग काम्पैक्ट एसयूवी बनकर उभरी, जहां इसकी कुल 19,810 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। इस दौरान इसने अपने सेगमेंट की अन्य मजबूत प्रतिद्वंद्वियों जैसे मारुति ब्रेजा और किया सोनेट को पीछे छोड़ दिया। ब्रेजा की 16,130 और सोनेट की 12,012 यूनिट्स बिकीं।

इसके अलावा नेक्सन, अपनी ही कंपनी की टाटा पंच के बाद देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूव्ही भी रही। नेक्सन को ग्राहकों के बीच खास बनाता है इसका दमदार इंजन और बेहतरीन परफार्मेंस। इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 बीएचपी की पावर और 170 एनएम का टार्क जनरेट करता है। वहीं, डीजल विकल्प के रूप में 1.5-लीटर इंजन मिलता है, जो 110 बीएचपी की पावर और 260 एनएम का टार्क देता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपये से शुरू होकर 15.60 लाख रुपये तक जाती है।

फीचर्स की बात करें तो नेक्सन का इंटीरियर काफी प्रीमियम और हाई-टेक है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, आटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही जेबीएल साउंड सिस्टम म्यूजिक अनुभव को और बेहतर बनाता है। सेफ्टी के मामले में नेक्सन अपनी कैटेगरी में मजबूत मानी जाती है। इसे 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है और इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे परिवारों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

महिंद्रा की ईवी सीरीज की 50,000 यूनिटस की बिक्री

नई दिल्ली। स्वदेशी वाहन निर्माता महिंद्र एंड महिंद्रा कंपनी की इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी सीरीज महिंद्रा बीई6, महिंद्रा एक्सईवी 9ई और महिंद्रा एक्सईवी 9एस ने मिलकर 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। नवंबर 2024 में लान्च हुई बीई 6 और एक्सईवी 9ई को बाजार से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी, जिनकी डिलीवरी मार्च 2025 से शुरू हुई। शुरुआती सात महीनों में ही इन दोनों माडलों की 30,000 से अधिक यूनिट्स बिक गईं, यानी औसतन हर 10 मिनट में एक गाड़ी की बिक्री हुई। बाद में एक्सईवी 9एस के जुड़ने से कुल बिक्री 50,000 तक पहुंच गई। इन वाहनों ने अब तक 32 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली है, जो उनकी विश्वसनीयता को साबित करता है। बीई 6 जहां स्पोर्टी डिजाइन और 682 किलोमीटर तक की रेंज के साथ युवाओं को आकर्षित कर रही है, वहीं एक्सईवी 9ई प्रीमियम सेगमेंट में कूप-स्टाइल डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जा रही है। एक्सईवी 9एस, कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसे खासतौर पर परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इस सफलता के पीछे ग्राहकों का बढ़ता भरोसा भी बड़ा कारण है। लगभग 80 प्रतिशत खरीदार पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन अपना रहे हैं।

राजस्थान की जीत के हीरो रहे बिश्नोई बोले गेंदबाजी में सुधार के लिए की कड़ी मेहनत

अहमदाबाद

राजस्थान रायल्स ने शनिवार रात खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले के हीरो लेग स्पिनर रवि बिश्नोई रहे, जिन्होंने चार महत्वपूर्ण विकेट लेकर प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार जीता।

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया को आउट कर मैच का रुख पलट दिया। मैच के बाद बिश्नोई ने कहा कि पिछला सीजन उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अपनी लेंथ और प्रदर्शन पर लगातार मेहनत की। उन्होंने बताया कि मानसिक, तकनीकी और शारीरिक—तीनों स्तर पर सुधार के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपने पसंदीदा विकेट के रूप में उन्होंने राहुल तेवतिया का नाम लिया। बिश्नोई के अनुसार, वह ऐसे मौकों के खिलाड़ी हैं। अगर वह उस समय आउट नहीं होते, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। बिश्नोई ने आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा, तुषार देशपांडे ने जिस तरह गेंदबाजी की और जोफ्रा आर्चर ने जैसे 19वां ओवर डाला, वह शानदार था। यह पूरी टीम का प्रयास था। हमारी टीम युवा है और हम आगे भी ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहना चाहते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रायल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल (55) और ध्रुव जुरेल (75) ने शानदार अर्धशतक लगाए, जबकि वैभव रघुवंशी ने 31 रनों की तेज पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। साई सुदर्शन ने 73 रन बनाए, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ा गया। अंत में राशिद खान (24) और कगिसो रबाडा (नाबाद 23) ने तेज रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, लेकिन टीम केवल 4 रन ही बना सकी और 20 ओवर में 8 विकेट पर 204 रन तक ही पहुंच पाई। इस तरह राजस्थान रायल्स ने 6 रन से रोमांचक जीत अपने नाम की। राजस्थान का अगला मैच सात अप्रैल को मुंबई इंडियंस से होगा।

न्यूज ब्रीफ

छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदला, छत्रपति शिवाजी महाराज खेल परिसर रखा गया

इंदौर । इंदौर के प्रसिद्ध खेल परिसर, जिसे पूर्व में छोटा नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसका आधिकारिक नामकरण अब छत्रपति शिवाजी महाराज खेल परिसर कर दिया गया है। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने शहर के सांस्कृतिक और खेल जगत के वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। आयोजन के दौरान उपस्थित जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जगाया शौर्य का भाव इस विशेष समारोह का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध लोक कलाकार और युवा शाहीर विक्रांत सिंह राजपूत रहे। उन्होंने समाज प्रबोधनकार की अपनी विशेष शैली में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों का सजीव वर्णन किया। विक्रांत सिंह राजपूत ने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से महाराज की युद्ध रणनीति, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जनता के समक्ष रखा। उनके गायन और प्रस्तुतिकरण के दौरान पूरा स्टेडियम जय भवानी, जय शिवाजी के उद्घोष से गुंजायमान रहा, जिससे उपस्थित युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ। वैचारिक क्रांति के प्रतीक है शिवाजी महाराज: स्वाती काशिद कार्यक्रम की आयोजक और भाजपा नगर मंत्री एडवोकेट स्वाती काशिद ने समारोह को संबोधित करते हुए इस नामकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल परिसर का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखना केवल एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का एक माध्यम है।

भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर का शानदार प्रदर्शन, लंबी कूद में जीता स्वर्ण पदक

बंगलूरू । इस सत्र में पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे मुरली श्रीशंकर ने शनिवार को शुरू हुई पहली इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.15 मीटर की कूद लगाकर खिताब अपने नाम किया। एनसीओई त्रिवेंद्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीशंकर ने अपने चौथे प्रयास में यह कूद लगाई। 2024 में घुटने की सर्जरी के बाद वापसी करने के बाद से यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले सत्र में 27 वर्षीय इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8.13 मीटर था। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सके थे श्रीशंकर श्रीशंकर को घुटने की चोट के कारण हुई सर्जरी की वजह से 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर रहना पड़ा था। उन्होंने पिछले साल सितंबर में टोक्यो विश्व चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था, लेकिन फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कांतीरवा स्टेडियम में श्रीशंकर मैदान में एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने आठ मीटर का आंकड़ा पार किया। बिहार के सनी कुमार 7.90 मीटर की कूद के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कर्नाटक के पुरुषोत्तम 7.87 मीटर से तीसरे स्थान पर रहे।

यूएस क्ले कोर्ट चैंपियनशिप : थियागो टिरांटे ने टाप सीड बेन शेल्टन को हराया, कई उलटफेर

ह्यूस्टन। यूएस पुरुष क्ले कोर्ट चैंपियनशिप में अर्जेंटीना के थियागो अगस्टिन टिरांटे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाप सीड बेन शेल्टन को हराकर बड़ा उलटफेर किया। टिरांटे ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी की और मुकाबला 6-7 (5), 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। शुरुआती सेट में कड़ी टक्कर के बाद हार झेलने वाले टिरांटे ने अगले दो सेट में जबरदस्त नियंत्रण दिखाया। उनकी सर्विस गेम इस मैच में सबसे मजबूत पहलू रही, जहां उन्होंने अपने सभी 16 सर्विस गेम जीतकर शेल्टन को वापसी का मौका नहीं दिया। शांत और संयमित खेल के दम पर उन्होंने मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया। दूसरी ओर, बेन शेल्टन के लिए यह हार निराशाजनक रही। फरवरी में डलास ओपन का खिताब जीतने के बाद से वह लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और इस टूर्नामेंट में भी राउंड आफ 16 से आगे नहीं बढ़ सके। अन्य मुकाबलों में भी कई दिलचस्प नतीजे देखने को मिले। अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा ने तीसरी वरीयता प्राप्त लर्नर टिएन को 7-5, 6-4 से हराया। वहीं, अमेरिका के टामी पाल ने टामस मार्टिन एचेवेरी को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया। रात के मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांसेस टियाफो ने लगभग तीन घंटे तक चले रोमांचक मैच में एलेक्सी पोपिरिन को 3-6, 6-4, 7-6 (6) से हराया।

एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2027 पर हार्दिक पांड्या की नजर, 10 ओवर गेंदबाजी के लिए कर रहे खास तैयारी

नई दिल्ली

भारतीय टीम के स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अभी से वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को स्पष्ट कर दिया है कि वह 2027 विश्व कप का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह पिछले कुछ महीनों से अपनी गेंदबाजी पर खास काम कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की सबसे बड़ी शर्त यह है कि पांड्या वनडे क्रिकेट में जरूरत पड़ने पर पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह फिट रहें। हालांकि हर मैच में उनसे पूरा स्पेल नहीं कराया जाएगा, लेकिन टीम को जब जरूरत हो, तब वह यह जिम्मेदारी निभा सकें। यही कारण है कि पांड्या अपनी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

इस दिशा में उनकी प्रगति का संकेत विजय हजारे ट्राफी में देखने को मिला, जहां उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके। इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि वह लंबा स्पेल डालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें इसी वजह से शामिल नहीं किया गया था क्योंकि तब वह 10 ओवर गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं माने गए थे। वर्ल्ड कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, जहां की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या जैसे सीम-बालिंग आलराउंडर की भूमिका टीम के लिए बेहद अहम हो सकती है। हालांकि, चयनकर्ता उनकी फिटनेस को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि वह पहले भी चोट के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रह चुके हैं। पांड्या के बैकअप के तौर पर चयनकर्ताओं की नजर नितीश कुमार रेड्डी पर भी बनी हुई है। उन्होंने भी घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी पर काम किया है और वर्कलोड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पांड्या के पिछले रिकार्ड पर नजर डालें, तो 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर उन्होंने 6 वनडे मैचों में 44 ओवर गेंदबाजी कर 4 विकेट लिए थे और उनका इकानमी रेट 4.90 रहा था। हालांकि बल्लेबाजी में वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके थे। कुल मिलाकर, हार्दिक पांड्या का फोकस साफ है फिटनेस, निरंतरता और आलराउंड प्रदर्शन के दम पर वह 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाना चाहते हैं।

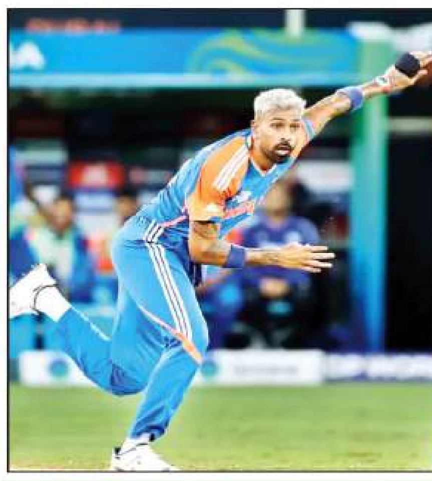

महिला खिलाड़ी के साथ सेल्फी के बाद अचानक बदला मैग्नस कार्लसन का मूड! अधिकारी से कहकर उसका मोबाइल हटवाया

नई दिल्ली। शतरंज की दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई चाल या जीत नहीं, बल्कि मैच से पहले का एक अजीब वाकया है। जर्मनी के कार्लजूए में खेले जा रहे ग्रेंके चेस फ्रीस्टाइल ओपन के दौरान कार्लसन और उनकी प्रतिद्वंदी एलुए नुरमान के बीच यह घटना हुई। मैच शुरू होने से ठीक पहले नुरमान ने कार्लसन से सेल्फी की रिक्वेस्ट की। कार्लसन ने मुस्कुराते हुए इसके लिए हामी भर दी और तस्वीर भी खिंचवाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक फोन जब्त करवाया सेल्फी लेने के बाद कार्लसन अपनी सीट से उठे और एक आर्बिटर (रेफरी) को लेकर लौटे। उन्होंने इशारा किया कि नुरमान के पास फोन है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके बाद आर्बिटर ने नुरमान से उनका फोन ले लिया और फिर मैच शुरू हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे पहले दोस्ती, फिर सख्ती वाला पल बता रहे हैं। नियम क्या कहते हैं दरअसल, शतरंज के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, मैच के दौरान खिलाड़ियों के पास फोन या कोई भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस रखना सख्त मना है। ऐसे में आर्बिटर का फोन हटाना पूरी तरह नियमों के अनुरूप था। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कार्लसन के इस व्यवहार को ओवर रिएक्शन भी बता रहे हैं। पहले भी दिखा चुका है गुस्सा यह पहली बार नहीं है जब कार्लसन अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में आए हों। पिछले साल फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी से हारने के बाद भी उनका गुस्सा देखने को मिला था। उस मैच में हार के बाद कार्लसन ने टेबल पर हाथ मारकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। कार्लसन का यह नया वीडियो दिखाता है कि वे नियमों को लेकर बेहद सख्त हैं, लेकिन उनके व्यवहार पर सवाल भी उठते रहते हैं।

सीएसके में कप्तानी को लेकर बढ़ा दबाव, संजू सैमसन की एंट्री से गायकवाड़ पर नजरें

नई दिल्ली

चेन्नई सुपर किंग्स में कप्तानी को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। एमएस धोनी जैसे दिग्गज कप्तान की विरासत संभालना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और अब रुतुराज गायकवाड़ पर यह जिम्मेदारी है। हालांकि, इस सीजन में सजू सैमसन के टीम में शामिल होने के बाद कप्तानी को लेकर प्रतिस्पर्धा और दबाव बढ़ गया है। भले ही मौजूदा सीजन में गायकवाड़ ही टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन सैमसन की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया है। क्रिकेट विशेषज्ञ माइकल वान और साइमन डूल का मानना है कि यह स्थिति गायकवाड़ के लिए मानसिक दबाव पैदा कर सकती है। वान के अनुसार, सैमसन को फ्रेंचाइजी भविष्य के कप्तान और धोनी के विकल्प के रूप में देख रही है, जिससे गायकवाड़ को अपनी जगह को लेकर सतर्क रहना पड़ सकता है। वान ने कहा कि यह एक अलग तरह की परिस्थिति है, जहां एक युवा कप्तान को अपनी भूमिका निभाते हुए यह भी ध्यान रखना होगा कि टीम में एक अनुभवी और सफल कप्तान मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि गायकवाड़ को कप्तानी जारी रखने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इस स्थिति का उन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। वहीं साइमन डूल ने भी इस बात से सहमति जताई कि सैमसन का टीम में आना एक बड़ा बदलाव है। सैमसन इससे पहले राजस्थान रायल के कप्तान के रूप में सफल रहे हैं और उन्होंने 2022 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। उनकी कप्तानी और विकेटकीपिंग क्षमता उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाती है। डूल का मानना है कि सैमसन के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं होगी। टीम बदलने के बाद खुद को साबित करना और नई भूमिका में ढलना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि सैमसन दक्षिण भारत से हैं और इस नई टीम में खुद को घर जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रदर्शन और भविष्य की भूमिका दोनों का दबाव रहेगा। कुल मिलाकर, चेन्नई सुपर किंग्स के भीतर यह बदलाव टीम के भविष्य को लेकर बड़ा संकेत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गायकवाड़ अपनी कप्तानी को कैसे संभालते हैं और सैमसन टीम में किस तरह की भूमिका निभाते हैं।

वेल्स में आईबी एफ वाल्टरवेट मुक्केबाजी

वेल्स में आईबी एफ वाल्टरवेट मुक्केबाजी में विरोधी पर प्रहार करती हुई लॉरेन प्राइस।

आईपीएल 2026 : अब टी20 में फिनिशर जैसी कोई भूमिका नहीं, स्टीफन फ्लेमिंग का बड़ा बयान

चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग का मानना है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में पारंपरिक फिनिशर की भूमिका अब पहले जैसी अहम नहीं रह गई है। उनका कहना है कि आज के खेल में बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं, जिससे मैच का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद फ्लेमिंग ने कहा कि अब टी20 क्रिकेट में हर बल्लेबाज पहली ही गेंद से बड़े शाट खेलने की कोशिश करता है। पहले जहां टीमें 15-16 ओवर तक पारी को संभालकर खेलती थीं और अंत में तेजी लाती थीं, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में शुरुआत से ही 10-12 रन प्रति ओवर की दर बनाए रखना जरूरी हो गया है, इसलिए टीमों को ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है जो पूरे मैच में आक्रामक खेल सकें।

सीएसके की टीम संरचना पर बात करते हुए फ्लेमिंग ने माना कि टीम में टाप आर्डर बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है, जिससे मिडिल और लोअर आर्डर में पारंपरिक फिनिशर की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि टीम के पास पर्याप्त बल्लेबाजी ताकत मौजूद है। उन्होंने बताया कि डेवाल्ड ब्रेविस चोट के कारण बाहर हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी फिट नहीं हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति टीम के संतुलन को प्रभावित कर रही है। फ्लेमिंग ने संजू सैमसन का भी समर्थन किया, जो शुरुआती मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि सैमसन नेट्स में अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और जब वह फार्म में आते हैं तो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उनके खराब प्रदर्शन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

कोच ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे खेल का संतुलन बल्लेबाजों के पक्ष में झुक गया है। उनका मानना है कि इस नियम ने मैच की गति और रणनीति दोनों को प्रभावित किया है, जिससे गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ गई है। वहीं, पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य की तेज पारी की भी चर्चा रही। इस पर उनके साथी शशांक सिंह ने कहा कि प्रियांश मानसिक रूप से बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं और अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कम उम्र में जिस तरह की परिपक्वता दिखाई है, वह काबिल-ए-तारीफ है। कुल मिलाकर, फ्लेमिंग का मानना है कि टी20 क्रिकेट का नया दौर पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी का है, जहां हर खिलाड़ी को शुरुआत से अंत तक तेज रन बनाने की जिम्मेदारी निभानी होती है।

हेनरिच क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से किया इनकार

नई दिल्ली

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की संभावनाओं को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि वह अब दोबारा राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे। 34 वर्षीय क्लासेन ने यह फैसला अपने परिवार को प्राथमिकता देने के कारण लिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय अनुबंध नहीं मिलने के बाद उन्होंने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और तब से वह दुनियाभर की टी20 लीग में सक्रिय हैं।

हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े एक वीडियो में क्लासेन ने नीतिश कुमार रेड्डी के साथ बातचीत के दौरान अपने फैसले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वापसी को लेकर उन्होंने करीब दो हफ्तों तक गंभीरता से विचार किया, लेकिन अंततः यह तय किया कि अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटना सही नहीं होगा। क्लासेन ने स्वीकार किया कि टी20 विश्व कप के दौरान अपने साथियों को अच्छा प्रदर्शन करते देख उनके मन में वापसी का विचार जरूर आया था। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वह टीम का हिस्सा क्यों नहीं हैं और उन्होंने दोबारा खेलने की इच्छा भी जताई थी। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम से भी बातचीत की थी।

हालांकि, क्लासेन ने बताया कि बातचीत के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और विश्व कप के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी वापसी की संभावना कम है। इसके चलते उन्होंने दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेलने का अंतिम निर्णय ले लिया। बता दें कि क्लासेन ने 2024 में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और अब वह पूरी तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। उनका यह फैसला दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ी अपने करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन को कितना महत्व देने लगे हैं।

पायल नाग ने जीता स्वर्ण पदक

बैंकाक। भारतीय पैरा तीरंदाजी में एक नया सितारा उभर कर सामने आया है। बैंकाक में महिला कम्पाउंड वर्ग के फाइनल में पायल नाग ने विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर पैरा तीरंदाजी सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में दो भारतीय आमने-सामने थे और 18 वर्षीय पायल ने ये मुकाबला 139-136 के अंतर से जीता। पायल का यह सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला स्वर्ण पदक है। 19 वर्षीय शीतल के हालिया शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह परिणाम और भी उल्लेखनीय है। शीतल बेहतरीन फार्म में थीं और 2025 के शानदार सीजन के बाद उन्हें विश्व तीरंदाजी की पैरा आर्चर आफ द ईयर भी चुना गया था। उन्होंने बैंकाक में भी उसी लय को बरकरार रखा और क्वालिफाइंग राउंड में 698 के शानदार स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जो कजाखस्तान की जनात ऐतिमोवा से 20 अंक अधिक था। वहीं, पायल ने 678 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था।

पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करती है इमली

भारत में काफी पुराने समय से इमली का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि इस फल का मूल देश अफ्रीका है, पर एशियाई देशों से जब यह फल फारस और अरब देशों में गया तो इसे इंडियन डेट कहा गया, जिसकी वजह थी कि यह फल देखने में खजूर के सूखे गूदे की तरह लगता था। भारतीय व्यंजनों में इसका उपयोग स्वाद लाने के लिए किया जाता है, पर सेहत के लिए लाभकारी अनेक गुण भी इसमें हैं। इमली की फली भूरे रंग की 3 से 7 इंच लंबी होती है। फलों के भीतर रसदार और अम्ल गूदे को चटनी और रसे (करी) में प्रयोग किया जाता है। इमली के गूदे में मौजूद टारटरिक और पेक्टिन की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है।

सेहत के लिए गुणकारी

इसकी पत्तियां ठंडक पहुंचाने वाली होती हैं, वहीं छाल एरिंस्ट्रेजेंट का काम करती है। इसके फल का गूदा पाचक, शीतल और रोगाणुरोधक होता है। इमली का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में पेट व पाचन समस्याओं के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां पेट के कीड़ों का नाश करती हैं। पीलिया में भी यह लाभकारी है। इसका उपयोग अल्सर की चिकित्सा के लिए भी किया जाता है।

पाचन विकार: पके हुए फल का गूदा पित्त की उल्टी, कब्ज, वायु विकार, अपचन के इलाज में लाभदायक है। पानी के साथ इसके गूदे को कोमल करके बनाया हुआ अर्क भूख में कमी होने में फायदा पहुंचाता है।

स्कर्वी: यह बीमारी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जिससे त्वचा में धब्बे आ जाते हैं, मसूड़े स्पंजी हो जाते हैं और श्लेष्मा झिल्ली से रक्त बहता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पीला और उदास दिखता है। इमली में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह स्कर्वी के इलाज में लाभदायक है।

सामान्य सर्दी: दक्षिण भारत में सर्दी के इलाज के लिए इमली को प्रभावकारी माना जाता है। पिसी हुई इमली के साथ 1 चम्मच काली मिर्च को पानी में कुछ समय उबालने के बाद इसका सेवन किया जाता है।

पेचिश: यह आंत में सूजन होने से होता है, जिससे दस्त के मल में अत्यंत बलगम या रक्त का निकास होता है। कभी-कभार साथ में बुखार और पेट दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इमली का पेय पेचिश के इलाज में लाभकारी है।

जलन: जलन के इलाज के लिए इमली के पत्तों को जला कर इसका महीन पाउडर बनाते हैं। इस पाउडर को तिल के तेल के साथ मिला कर जले हुए हिस्से में लगाने पर घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाता है।

जोड़ों की सूजन: इमली के पत्तों को पानी के साथ पीस कर बने लेप को जोड़ों और टखने के सूजे हुए हिस्से में लगाने पर सूजन और दर्द में राहत मिलती है।

गले की खराश: इमली के पानी के गरारे गले की खराश के इलाज में लाभकारी हैं। आप चाहें तो इमली को पानी में उबाल कर इसके गरारे कर सकते हैं अथवा इसकी सूखी पत्तियों का पाउडर पानी में मिला कर उपयोग में लाया जा सकता है।

खास हैं ये हिकारू स्कर्ट्स...

जापान में इन दिनों फैशन में एक नया ट्रेंड शामिल हुआ है। ये हैं एलईडी स्कर्ट्स जिन्हें हिकारू स्कर्ट्स का नाम दिया गया है। यह स्कर्ट्स जापान के डिजाइनर कियोयुकी अमानो ने डिजाइन की हैं। स्कर्ट्स को बनाने में एलईडी लाइट्स का प्रयोग किया गया है । इनमें नीचे अन्दर की ओर एलईडी लाइट्स लगी हैं। पैरों पर पड़ती हैं लाइट्स इसकी खासियत है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्कर्ट में दी गयी लाइट सीधे पहनने वाले के पैरों पर पड़ती हैं।

तरबूज खाने के अनूठे फायदे

तरबूज में लाइकोपिन पाया जाता है जो त्वचा की चमक को बरकरार रखता है। हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में भी तरबूज एक रामबाण उपाय है। ये दिल संबंधी बीमारियों को दूर रखता है। दरअसल ये कोलस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है जिससे इन बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। विटामिन और की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये शरीर के इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है।

फाइबर यानी रेशे से होने वाले लाभ पर शायद ही किसी को संदेह हो। पाचन प्रक्रिया और हृदय रोगों में होने वाले लाभ के कारण फूड कंपनियां बड़े स्तर पर उच्च फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ बाजार में उतार रही हैं। क्या खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले कृत्रिम फाइबर, प्राकृतिक फाइबर जितना ही लाभ पहुंचाते हैं?

फाइबर से दोस्ती

फाइबर यानी रेशा हमारे भोजन का अहम हिस्सा है। स्पंज की तरह काम करते हुए फाइबर प्राकृतिक तरीके से शरीर की सफाई करने में मदद करता है। साबुत अनाज, चोकर, फल व सब्जियां, दालें व बींस (राजमा व लोबिया) में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल्कि फाइबरयुक्त चीजें खाने के बाद आपको कुछ देर तक भूख नहीं लगती। यही वजह है कि आहार विशेषज्ञ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने और वजन कम करने के इच्छुकों को उच्च फाइबरयुक्त डाइट की सलाह देते हैं। अलसी, आलूबुखारा, चोकर, साबुत अनाजों में फाइबर की मौजूदगी आंतों को मजबूती देती है।

रेशा पौधों से मिलने वाला वह भाग है, जिसे मानव शरीर में मौजूद एंजाइम पचा नहीं पाते। शरीर में पहुंच कर यह रेशा नमी को ग्रहण कर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। दिनभर में 30 ग्राम फाइबर का सेवन उपयुक्त होता है।

फाइबर के प्रकार

इनसॉल्युबल फाइबर: साबुत अनाज व उससे बने पदार्थों, बीज, ताजे फल व सब्जियों में इसकी अधिकता होती है। इससे खाद्य पदार्थ पचाने में आसानी होती है, जिससे आंतों पर कम दबाव पड़ता है और कब्ज नहीं होता। शोध बताते हैं कि कम वसा और अधिक फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थों से वायु संबंधी रोग नहीं होते। साथ ही कई तरह के कैंसर को रोकने में भी मदद मिलती है।

सॉल्युबल फाइबर: पानी में घुलनशील ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में विशेष उपयोगी होते हैं। जई की भूसी और सूखे बींस (लोबिया और राजमा) में इसकी अधिकता होती है। इससे पेट से भोजन धीरे-धीरे आगे मूव करता है और ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रखने में मदद मिलती है।

शरीर में फाइबर का काम

वजन कम करना: फाइबर स्पंज की तरह काम करते हुए पाचन तंत्र में मौजूद नमी .को ग्रहण करता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी रहती है। इससे भोजन से मिलने वाली संतुष्टि बढ़ती है, जो विभिन्न वजन कम करने वाले प्रोग्राम्स से भी नहीं मिलती। फाइबर से शरीर की वसा और शर्करा को ग्रहण करने की प्रक्रिया में सुधार होता है। पाचन प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे शर्करा धीरे-धीरे रक्त में पहुंचती है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और शर्करा की कमी के कारण होने वाली थकावट व कमजोरी नहीं होती। फाइबरयुक्त भोजन को चबाने में अधिक समय लगता है। ऐसे में एक ओर खाना खाने की गति में कमी आती है तो दूसरी ओर खाने से मिलने वाली संतुष्टि बढ़ जाती है।

शरीर होता है टॉक्सिन फ्री: खाद्य पदार्थों में मौजूद रेशा पानी को ग्रहण कर अपशिष्ट पदार्थों को मुलायम बनाता है। इससे अपशिष्ट पदार्थ आंतों में अधिक समय तक नहीं रहते और उनके बाहर निकलने में आसानी होती है। मलाशय पर अधिक जोर नहीं पड़ता। फाइबर की कमी से मल शुष्क व कड़ा हो जाता है, जिसमें विभिन्न दवाओं, विषाक्त व हानिकारक रसायन आदि कई तरह के संक्रमणों की मौजूदगी होती है। फाइबर से अपशिष्ट पदार्थ मलाशय से बाहर निकलने में कम समय लेते हैं। इससे प्राकृतिक तरीके से आंतों की सफाई हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण कम होने के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल स्थिर रहता है।

आइसोलेटेड बनाम डायटरी फाइबर

फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां बड़े स्तर पर फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ बाजार में उतार रही हैं। दही, आइसक्रीम, अनाज और जूस आदि में बड़ी मात्रा में आइसोलेटेड फाइबर मिलाए जा रहे हैं। आइसोलेटेड फाइबर के रूप में डिब्बों पर इन्युलिन, पेक्टिन, पॉली-डेक्सट्रोस, मिथाइलसेल्युलॉस और माल्टोडेक्सट्रिन नाम देखने को मिलते हैं। आइसोलेटेड फाइबर, खाद्य पदार्थों से प्राकृतिक रूप में भी मिलते हैं और कृत्रिम रूप से भी इन्हें बनाया जाता है। पर प्रश्न यह है कि कृत्रिम रूप से मिला कर बनाए गए फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ भी क्या प्राकृतिक फाइबर जैसा लाभ पहुंचाते हैं?

इसमें दो राय नहीं कि कंपनियों के फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ शरीर को फाइबर देते हैं। जिन लोगों की डाइट में फाइबर की कमी रहती है, उनमें इनके लाभ भी देखने को मिलते हैं, मसलन इन्युलिन फाइबर से शरीर में फेंड्ली बेक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है। कोलन यानी मलाशय में पदार्थ को कैंसरकारी बनने से रोकने में भी यह असरदार है। शोध कहते हैं कि इन्युलिन की मौजूदगी भोजन से मिलने वाली संतुष्टि को बढ़ा देती है व इसमें केल्शियम और मैग्नीशियम आदि मिनरल को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है।

फाइबर के लाभ

- पाचन प्रकिया नियमित होती है।
- अपशिष्ट पदार्थ देर तक आंतों में जमा रहकर टॉक्सिन नहीं फैलाते।
- कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, हृदय रोगों में लाभकारी है।
- मलाशय के कैंसर को दूर करता है।
- वजन कम करने में मदद मिलती है।

रिफाइंड प्रोडक्ट्स में फाइबर कम

रिफाइंड खाद्य पदार्थों में फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, मसलन मैदे से बनी ब्रेड। इसीलिए सफेद ब्रेड की जगह होलग्रेन ब्रेड को लेने की सलाह दी जाती है। कंपनियां सेहत के अलावा कई अन्य कारणों से भी पदार्थों में फाइबर मिलाती हैं, जैसे आइसक्रीम आदि डेजर्ट में फाइबर वसा और शर्करा कम करने के लिए मिलाए जाते हैं। इसी तरह दही, योगर्ट और पुडिंग को गाढ़ा करने व पिज्जा को क्रिस्प बनाने के लिए भी फाइबर मिलाते हैं।

प्राकृतिक फाइबर के हैं फायदे अनेक

जहां कंपनियां वस्तुओं में एक या दो तरह के फाइबर मिलाती हैं, वहीं बींस, चोकर, साबुत अनाज व फल-सब्जियों में कई तरह के लाभदायक फाइबर एक साथ मिलते हैं। विभिन्न फाइबर के लाभ भी अलग होते हैं, जैसे हर फाइबर कब्ज को दूर करने में उपयोगी नहीं है। मटर और जई इसमें लाभ पहुंचाते हैं, पर माल्टोडेक्सिट्रिन के सेवन से इसमें लाभ नहीं मिलता। ध्यान रखें कि आइसोलेटेड फाइबर की अधिकता एसिडिटी कर सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनके डिब्बों पर आप ओलिगोफ्रूक्टस, पॉलीडेक्सट्रॉस और इन्युलिन पाते हैं, उनका अधिक मात्रा में सेवन करना वायु रोग और सूजन की परेशानी कर सकता है।

यूं बढ़ाएं फाइबर की मात्रा

ब्रेकफास्ट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। होलग्रेन ब्रेड टोस्ट, ताजे फल व फाइबरयुक्त पदार्थ जैसे दलिया व भूसी मिलाएं। फलों के ऊपरी हिस्से, बीज और गूदे में फाइबर सबसे अधिक होता है। चोकर सहित रोटी बनाएं। सलाद, कॉर्नफ्लेक्स, पोहा, चपाती, उपमा, ज्वार और जौ का सेवन करें। खाने में बादाम और अंकुरित भोजन की मात्रा बढ़ाएं। डाइट में फाइबर के साथ पानी की मात्रा भी बढ़ाएं। कुछ सब्जियों और फलों के छिलके में अधिक फाइबर होता है। जरूरी है कि आप छिलके सहित फल खाएं और फलों को अच्छी तरह धो लें। बीजों में भी फाइबर होता है, उदाहरण के तौर पर टमाटर से बीज।

इनसे पाएं नेचुरल फाइबर

फली/ बींस/दालें: बींस (राजमा और लोबिया) में सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है। एक कप राजमा व लोबिया में 15 ग्राम से अधिक फाइबर मिलता है। इसी तरह दाल विशेषकर मसूर की दाल में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। सब्जियों में मटर में सबसे अधिक फाइबर होता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां व फल: हरी पत्तेदार सब्जियों में लोह तत्व, बेटा केरोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एक कप उबली हुई हरी सब्जियां जैसे पालक, पत्तेदार शलजम और चुकंदर में 4 से 5 ग्राम फाइबर मिलता है। इसी तरह नाशपाति और सेब से भी फाइबर मिलता है। एक बड़े सेब से जहां 3.3 ग्राम फाइबर मिलता है, वहीं मध्यम आकार की नाशपाति से 5.1 ग्राम फाइबर मिल जाता है।

मेवा: बादाम, पिस्ता और अखरोट में केवल प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें फाइबर भी प्रचुर पाया जाता है। किशमिश में सॉल्यूबल और नॉन सॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। किशमिश से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है।

रागी: रागी में सेल्युलॉस होता है, जो कि एक तरह का फाइबर है। रागी का नियमित सेवन कब्ज को दूर रखता है। इसके अलावा रागी में कैल्शियम, लोहा और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रागी का सेवन मधुमेह और मोटापे के शिकार लोगों के लिए भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसका पाचन धीरे-धीरे होता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्त्राव धीमा हो जाता है।

जई: ओट्स में आहारक फाइबर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी 1 भी होता है। जई में वसा कम होती है, इससे शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद मिलती है। इससे कार्डियोवस्कुलर रोगों को कम करने में मदद मिलती है।

ब्लेम गेम से बचें...

परिवार में ऐसे दौर आते हैं जब वे संकट से गुजरते हैं। चाहे आर्थिक संकट हो या रिश्तों में दरार, विचारों की अलहदगी, किसी प्रिय की बीमारी या मृत्यु। बजाय इसके कि ये सारी चीजें आपसे भरपूर नेगेटिव टोल वसूल सके इससे पहले ही परिवारों की एकजुटता और संकट से बाहर आने की युति आपको ऐसे अप्रिय स्थितियों से भी उचित तरीके से बाहर आने में मदद करेगी। तनाव के लिए कभी भी खुद को या किसी और को दोषी ना ठहराएं। परिस्थितियां जरूर खराब हो सकती हैं लेकिन लोग नहीं। किसी को दोष देना स्थिति और रिश्तों को और भी खराब बना सकता है।

तनाव की चेतावनी

जब हमारा शरीर और दिमाग इन स्थितियों से बाहर आने में असमर्थ हो जाए तो तनाव झलकने लगता है। बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लगती है जो हमें चेतावनी देते हैं कि हम मुसीबत में हैं। ये हार्मोन्स बताते हैं कि हमें इन तनावभरी स्थितियों से बाहर आने के लिए सही टेक्नीक अपनाने की जरूरत है। तनाव पूरी तरह से खराब नहीं है। ये आपको प्रोत्साहित भी करता है। इसके जरिए हम अपनी लिमिट्स जान पाते हैं। ये परिवार और दोस्तों के साथ आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का काम करता है। अनवरत चलते रहने वाला तनाव आपको असहाय होने का अहसास कराता है और जो हमारे पास हैं उन्हें भी परेशानी से भर देता है। आप खुद को कंट्रोल करते हैं या फिर तनाव आपको कंट्रोल करता है? अगर आप ये समझ पाते हैं कि आपका परिवार तनाव से गुजर रहा है तो उनसे बात करें, परिस्थितियों पर गौर करें और तनाव खत्म करने की कोशिशें करें।

सिचुएशन को स्वीकारें

अवांछित तनाव के संकेतों को पहचान पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई मुश्किल है तो उसे स्वीकार करें। याद रखें कि परिवार में किसी प्रिय की मौत या बीमारी आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। आप अपने बॉस के मूड को ठीक नहीं रख सकते ना ही स्टॉक मार्केट को एक स्तर से बाहर जाने से रोक सकते हैं। तो फिर इन परिस्थितियों के सामने आने पर तनाव में डूब जाना कहां तक सही है। ज्यादा खर्च की वजह से आप आर्थिक संकट में आ सकते हैं, इस पर रोक लगाकर तनाव को जरूर टाला जा सकता है। जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें करके तनाव को दूर करने की कोशिश जरूर करें। जाहिर है कुछ चीजों को स्वीकारना जरूरी है।

चीजों को देखें

जिस किसी चीज की वजह से आप भयंकर तनाव में हैं जो आपके परिवार को भी तनाव में ला देती है उन्हें देखें और दूर करने की कोशिश करें। परिवार के साथ चीजों पर विचार करें। दूसरों को बताएं कि आप क्यों चिंतित हैं, उन्हें बताएं कि आप इस स्थिति को दूर कर पाएंगे। अपनी उम्मीदों और प्राथमिकताओं पर एक बार फिर से विचार करें। आर्थिक वजह से तनाव है तो परिवार वालों का सहयोग लें। वे आपकी जरूरत को समझेंगे। ईमानदारी से और आगे रहते हुए प्रयास करें।

लोगों तक पहुंचे

कोई परिस्थिति होपलेस नहीं होती। दोस्तों और करीबियों का हाथ थामें और मजबूत हो जाएं। कभी-कभी दूसरों से बात करना और उनकी सुनना भी कारगर उपाय बन जाता है। बातों ही बातों में कई सॉल्यूशन्स मिल जाते हैं जिन पर आपका ध्यान अभी तक गया ही नहीं था। आपके करीबी आपके तनाव का कारण अच्छे से और जल्दी पकड़ पाएंगे क्योंकि वे आपको भी बेहतर समझते हैं। तो जब भी तनावग्रस्त हों परिवार के नजदीक पहुंच जाएं।

सकारात्मक बनें

तनाव अपने आप कभी नहीं जाता। इसे मुस्कुराहट हंसी के ठहाकों, योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से दूर भगाया जा सकता है। तनाव से खुद को दूर कर लें। अकेले सैर पर निकल जाएं। जो चीजें आपको रिलेक्स रखती हैं, करें। संगीत सुने, गेम खेलें, स्वीमिंग करें, दौड़ लगाएं। पॉजिटिव चीजों को करीब रखें ये आपका मूड हल्का और शानदार बनाएंगी। फायनेंशियल क्राइसिस आपको तनाव देता है लेकिन कुछ सबक भी सिखाते हैं। परिवार में अचानक से आई मेडिकल इमरजेंसी आपको सही समय पर हेल्थ इन्स्योरेंस ले लेने का सबक देती है और सिखाती है कि समय पर परिवार के लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच जरूरी है।

इश्यूज पर ध्यान दें

तनाव के लिए कभी भी खुद को या किसी और को दोषी ना ठहराएं। परिस्थितियां जरूर खराब हो सकती हैं लेकिन लोग नहीं। किसी को दोष देना स्थिति और रिश्तों को और भी खराब बना सकता है। शादी या रिश्तों का टूटना आपसे बहुत कुछ वसूल सकता है इमोशनली और फिजीकली भी। इस दौर से आपका कोई परिचित गुजर रहा है तो उसे सपोर्ट करें। परिस्थितियों को दोष देने की बजाय इश्यूज पर ध्यान दें। अगर आपके सिगरेट पीने की वजह से आपके बच्चे को अस्थमा हो गया है तो परिस्थिति को दोष देने से क्या होगा।

संभालें, सहारा दें

अगर परिवार का कोई सदस्य तनाव में है तो उसे संभाले, सहारा दें। उसे समझने की कोशिश करें। परिवार आपके लिए है और आप परिवार के लिए। परिवार के लोग हर अच्छे-बुरे समय में एकदूसरे के साथ होते हैं। ये सपोर्ट किसी को भी बुरे वक्त से बाहर आने का संबल देता है।

रेसिपी

पिज्जा सैंडविच

सामग्री

पिज्जा बेस- 1, हरी कटी प्याज- आधा कप, शिमला मिर्च बारीक कटी -आधा कप, टमाटर (बरीक कटा)- आधा कप, टमाटर की चटनी- आधा कप, ग्रीन चिली सॉस- एक बड़ा चम्मच, नमक-(स्वादनुसार), काली मिर्च (स्वादनुसार), मक्खन (एक बड़ा चम्मच)

विधि

सबसे पहले फ्राई पैन में मक्खन गर्म करें। अब कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और नमक डालकर अच्छ से भूनें। जब ये पूरी सामग्री अच्छे से भुन जाए तो आंच से उतार लें। अब पिज्जा बेस को चार तिकोने टुकड़ों में काटकर टोस्टर में ग्रिल करें। सैंडविच तैयार करने के लिए ग्रिल पिज्जा टोस्ट पर टमाटर की चटनी और ग्रीन चिली सॉस लगाकर भुनी हुई सब्जियां डालें। और फिर काली मिर्च ऊपर से छिड़कर दूसरा ग्रिल्ड टोस्ट ऊपर से रखे। और बस लीजिए हो गया आपका पिज्जा सैंडविच तैयार।

चॉकलेट की गुजिया

समाग्री

500 ग्राम मैदा
एक किलो मावा (खोया)
250 ग्राम चॉकलेट चिप्स
4 बड़े चम्मच किशमिश
100 ग्राम बादाम कटे हुए
500 ग्राम चीनी (पिसी हुई)
तेल या घी

विधि

गुजिया की बाहर की परत बनाने के लिए सबसे पहले मैदा छान लें, फिर इसमें घी या तेल मिलाएं और फिर जरूरत के हिसाब से पानी डालते हुए नर्म गूंद लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दें। अब भरावन तैयार करने के लिए गैस पर कढ़ाही गर्म करें। इसमें मावा डालकर मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक की वो ब्राउन न हो जाए। फिर इसमें चॉकलेट चिप्स डालकर 2 मिनट भूनें। इसके बाद चीनी, काजू और किशमिश डालकर मिलाएं, और चलाते रहें। जब मावा भूनकर सूख जाए तो गैस बंद कर दें और सामग्री को ठंडा होने दें। इसके बाद तैयार मैदे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल आकार देने के बाद छोटी रोटी में बेल लें। अब गुजिया बनाने का सांचा लें और इसमें दोनों तरफ हल्का तेल लगाएं। अब बेली हुई रोटी को इस सांचे में रखें और एक चम्मच के करीब भरावन रोटी के बीच में डालें और सांचा बंद कर दें। सांचा बंद करने के बाद रोटी का जो भी हिस्सा बाहर रह जाए, उसे हटा दें। इसी तरह सारे आटे से गुजिया तैयार करें और एक गीले कपड़े पर रखते जाएं। अब कढ़ाही में तेल या घी गर्म करें और मध्यम आंच पर एक बार में 4-5 गुजिया डीप फ्राई कर लें। जब गुजिया सुनहरी होने लगे तो इन्हें प्लेट में निकाल लें। इसी तरह सारी गुजिया तलें। और बस तैयार हैं आपकी चॉकलेट गुजिया।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**